



BJS

Bharatiya Jain Sanghathan

Benefits of Minority for Education Institutions

2014

Compiled from Internet and Published by :

Shri. Shantilal Muttha for Bharatiya Jain Sanghathan (BJS)
Muttha Towers, Don Bosco Road, Near Golf Course,
Yerawada, Pune - 411 006. India.
Tel.: 020 - 4120 0600
Email: info@bjsindia.org
Website: www.bjsindia.org

Printed at:

Prabhat Printing Works,
427, Gultekdi, Pune 411 037. India.

For Private Circulation only.

Price : ₹ 100/-

(Set of 6 Books ₹ 200)

Edition : March 2014

INDEX		
Sr. No.	Name	Page No.
Chapter 1	Preface	2
Chapter 2	Constitutional Provisions	5
Chapter 3	Prime Minister's New 15 Point Programme	7
Chapter 4	Scheme Of Infrastructure Development for Schools or Institutions	12
Chapter 5	Scheme Of Infrastructure Development Private Aided/Unaided Minority Institutes (IDMI)	14
	Chapter 5a-Application Form Of Development for Infrastructure in Minority Educational Institutions of Elementary/ Secondary and Higher Secondary Level	19
Chapter 6	Schemes Of Research and Studies	24
	Chapter 6a-Form for Submission of Proposals for Operation Research/ Market Research/ Action Research/ Survey	38
	Chapter 6b-Form for Submission of Proposals for Workshops/ Seminars / Conferences	42
	Chapter 6c-Application Form of Schemes for Research and Studies	44
Chapter 7	Application Form for Minority Status Certificate	47
Chapter 8	Application Form to be Submitted by Coaching Institutes for Receiving Grant-In-Aid	50
Chapter 9	FAQs in General for Educational Institutes	55
Chapter 10	FAQs for Linguistics Minorities	65
Chapter 11	Addresses	70
	Chapter 11a-Addresses Of National Commission For Minorities	70
	Chapter 11b-Addresses Of State Minorities Commission	71
	Chapter 11c-Addresses Of State Channelising Agencies Of NMDFC	74
Chapter 12	Gazette of India For Jain Minority	79
Chapter 13	About Bharatiya Jain Sanghathan (BJS)	80

Chapter 1

Preface

२७ जनवरी २०१४ को भारत सरकार ने जैन समाज को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, शिक्षा, स्वरोजगार एवं सक्षमीकरण के कई विशेष प्रावधान हैं। इसे क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग एवं अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। जनवरी २०१४ तक मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख एवं पारसी धर्मों को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था। अब जैन धर्म को भी यह अधिकार प्राप्त है।



जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए या नहीं इस पर मतभिन्नता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि, जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होने से जैन समाज मुख्य प्रवाह से दूर हो जायेगा। कुछ लोगों को लगता है कि, इस घोषणा से जैन समाज को आरक्षण का दर्जा मिलेगा जो कि निम्न जाति के लाभ के लिए है। यह मतभिन्नता संपूर्ण जानकारी के अभाव की वजह से है। अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने की वजह से, जैन समाज इस देश के मुख्य प्रवाह से दूर हो जायेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। ना ही अल्पसंख्यक याने आरक्षण है। इसके विपरीत अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से जैन समाज के सभी धर्मस्थल, धार्मिक संस्थाएँ, संस्कृति, भाषा व लिपी सुरक्षित रहेगी। जैन समाज अपनी रूचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकेगा और उसका प्रशासन भी कर सकेगा। जैन समाज आर्थिक दृष्टि से सुसंपन्न समाज है, ऐसी धारणा है, यह अंशतः सत्य भी है। तथापि इस समाज में बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है व अल्प आय प्राप्त करने वाला वर्ग भी है। जिन्हें दैनंदिन जीवन जीने के लिए अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के उत्थान की अनेक योजनाओं के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का प्रावधान बजट में किया जाता है।

अल्पसंख्यक दर्जा मिलने की वजह से अब जैन समाज को भी इन सारी योजनाओं में हिस्सा लेने का एवं विविध योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह जैन समाज के उत्थान के लिए बड़ी बात है।

देश में आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा इन राज्यों में जैन समाज को पहले से ही राज्यस्तर पर अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था। इन सभी राज्यों में राज्यस्तर के अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ उन उन राज्यों के जैन समाज के लोगों को मिल रहा है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की योजनाओं में काफी भिन्नता है। अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए राज्य स्तर की योजनाओं से काफी ज्यादा योजनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं। जैन समाज के विद्यार्थियों की शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की विविध योजनाएँ, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन की विविध योजनाएँ, युवतियाँ एवं महिलाओं के सक्षमीकरण की योजनाएँ, व्यवसाय के विकास की विभिन्न योजनाएँ, धर्मस्थान की सुरक्षा की विभिन्न योजनाएँ एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से समाज उत्थान की विविध योजनाएँ उपलब्ध हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने की वजह से इन सभी योजनाओं की जानकारी जैन समाज के घर घर तक पहुँचाना आवश्यक है।

भारतीय जैन संघठन सन १९८५ से देशभर में सामाजिक उत्थान एवं शैक्षणिक विकास का कार्य कर रहा है। देश में जैन समाज के विभिन्न संस्थाओं द्वारा २५०० शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण सौ डेढ़सौ वर्ष पूर्व किया गया। इन शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, सभी जाति-धर्म के जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा, सेवा के रूप में प्रदान की जाती है। भारतीय जैन संघठन द्वारा सन २००२ में फेडरेशन ऑफ जैन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट की स्थापना की गई। जैन समाज की १७०० शैक्षणिक संस्थाएँ इस फेडरेशन का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने की वजह से इन शैक्षणिक संस्थाओं को विकास के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।

केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक कानून, अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक आयोग, प्रधानमंत्री १५ सूत्री कार्यक्रम एवं संबंधित अन्य विभाग तथा वेबसाइट का अध्ययन कर, भारतीय जैन संघठन द्वारा ६ पुस्तकों का संकलन किया गया है। आशा है कि, निम्नलिखित पुस्तकों के माध्यम से अल्पसंख्यक योजनाओं व लाभ की जानकारी जैन समाज के सभी वर्गों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन विद्यार्थियों को लाभ
- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन समाज की शिक्षण संस्थाओं को लाभ
- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन समाज की धार्मिक संस्थाओं को लाभ
- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन महिलाओं को लाभ
- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन व्यवसायियों को लाभ
- अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन सामाजिक संस्थाओं को लाभ

आप यह पुस्तकें भारतीय जैन संघठन के मुख्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा www.bjsindia.org वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर संपर्क करें।

भारतीय जैन संघठन,

मुथ्था टॉवर्स, डॉन बॉस्को मार्ग, गोल्फ कोर्स के पास, चेखडा, पुणे - ४११ ००६.

आपसे विनम्र निवेदन है कि, उपरोक्त जानकारी जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करें।

धन्यवाद,

शांतीलाल मुथ्था

संस्थापक

Chapter 2

Constitutional Provisions

The Basis for Benefits to Minorities: The Provisions made in the Constitution of India.

The all encompassing Constitution of India has made provisions through some Articles that allow for granting of additional benefits to minority communities. The Articles of the Constitution of India under which benefits provided to educational Institutes having a Minority certification are :

The Articles 29 and 30 of the Indian Constitution cover cultural and education rights. Articles 347, 350 and 350A relate to usage of a language as medium of instruction, for communication and for representation to redress of grievances.

Art.29 Protection of interests of minorities:

- 1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.
- 2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

Art.30 Right of minorities to establish and administer educational institutions:

- (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
- (1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, referred to in clause (1), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.

- (2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

Art.347 Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State:

On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognized by that State, direct that such language shall also be officially recognized throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Art.350 Language to be used in representations for redress of grievances:

Every person shall be entitled to submit a representation for the redressal of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Art.350A Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage:

It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

Chapter 3

Prime Minister's New 15 Point Programme

(A) Enhancing opportunities for Education.

(1) *Equitable availability of ICDS Services*

The integrated Child Development Services (ICDS) Scheme is aimed at holistic development of children and pregnant/lactating mothers from disadvantaged section, by providing services through Anganwadi Centers such as supplementary nutrition, immunization, health check-up, referral services, pre-school and non-formal education. A certain percentage of the ICDS projects and Anganwadi Centers will be located in blocks/villages with a substantial population of minority communities to ensure that the benefits of the scheme are equitably available to such communities also.

(2) *Improving access to School Education*

Under the Sarva Shiksha Abhiyan, the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme, and other similar Government schemes, it will be ensured that a certain percentage of such schools are located in villages/localities having a substantial population of minority communities.

(3) *Greater resources for teaching Urdu*

Central assistance will be provided for recruitment and posting of Urdu language teachers in primary and upper primary schools that serve a population in which at least one-fourth belong to that language group.

(4) *Modernizing Madarsa Education*

The Central Plan Scheme of Area Intensive and Madarsa Modernization Programme provides basis educational infrastructure in areas of concentration of educationally backward minorities and resources for the modernization of Madarsa education. Keeping in view of importance of addressing this need, this programme will be substantially strengthened and implemented effectively.

(5) *Scholarships for meritorious students*

from minority communities Schemes for pre-matric and post-matric scholarships for students from minority communities will be formulated and implemented.

(6) *Improving educational infrastructure through the Maulana Azad Education Foundation.*

The Government shall provide all possible assistance to Maulana Azad Education Foundation (MAEF) to strengthen and enable it to expand its activities more effectively.

(B) Equitable Share in Economic Activities and Employment

(7) *Self-Employment and Wage Employment for the poor*
The Swarnjayanti Gram Swarajgar Yojna (SGSY)

The primary self-employment programme for rural areas, has the objective of bringing assisted poor rural families above the poverty line by providing them income generating assets through a mix of bank credit and Governmental subsidy. A certain percentage of the physical and financial targets under the SGSY will be earmarked for beneficiaries belonging to the minority communities living below the poverty line in rural areas.

The Swarnjayanti Shahary Rohgar Yojna(SSRY) consists of two major components namely, the Urban Self-Employment

Programme (USEP) and the Urban Wage Employment Programme(UWEP). A certain percentage of the physical and financial targets under USEP and UWEP will be earmarked to benefit people below the poverty line from the minority communities.

The Sampurna Grameen Rozgar Yojna(SGRY) is aimed at providing additional wage employment in rural areas alongside the creation of durable community, social and economic infrastructure. Since the National Rural Employment Guarantee Programme (NREGP) has been launched in 200 districts, and SGRY has been merged with NREGP in these districts, in the remaining districts, a certain percentage of the allocation under SGRY will be earmarked for beneficiaries belonging to the minority communities living below the poverty line till these districts are taken up under NREGP. Simultaneously, a certain percentage of the allocation will be earmarked for the creation of infrastructure in such villages, which have a substantial population of minorities.

(8) Up-gradation of skill through technical training

A very large proportion of the population of minority communities is engaged in low-level technical work or earns its living as handicraftsmen. Provision of technical training to such people would upgrade their skills and earning capability. Therefore, a certain proportion of all new ITIs will be located in areas predominantly inhabited by minority communities and a proportion of existing it is to be upgraded to 'Centres of Excellence' will be selected on the same basis.

(9) Enhanced credit support for economic activities

The National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) was set up in 1994 with the objective of promoting economic development activities among the minority communities. The Government is committed to strengthen the NMDFC by providing it greater equity support to enable it to fully achieve its objective.

Bank credit is essential for creation and sustenance of self-employment initiative. A target of 40% of net bank credit for priority sector lending has been fixed for domestic banks. The priority sector includes, inter alia, agricultural loans, loan to small-scale industries & small business, loans to retail trade, professional and self-employed persons, education loans, housing loans and micro-credit. It will be ensured that an appropriate percentage of the priority sector lending in all categories is targeted for the minority communities.

(10) Recruitment to State and Central Services

In the recruitment of police personnel, State Governments will be advised to give special consideration to minorities. For this purpose, the composition of selection committees should be representative.

The Central Government will take similar action in the recruitment of personnel to the Central police forces. Large scale employment opportunities are provided by the Railways, nationalized banks and public sector enterprises. In these cases also, the concerned departments will ensure that special consideration is given to recruitment from minority communities.

An exclusive scheme will be launched for candidates belonging to minority communities to provide coaching in Government institutions as well as private coaching institutes with credibility.

(C) Improving the conditions of living of minorities.

(11) Equitable share in rural housing scheme

The Indira Awaas Yojna (IAY) provides financial assistance for shelter to the rural poor living below the poverty line. A certain percentage of the physical and financial targets under IAY will be earmarked for poor beneficiaries from minority communities living in rural areas.

(12) *Improvement in condition of slums inhabited by minority communities.*

Under the schemes of Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) and Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission (JNURM), the Central Government provides assistance to States/UTs for development of urban slums through provision of physical amenities and basic services. It would be ensured that the benefits of these programmes flow equitably to members of the minority communities and to cities/slums, predominantly inhabited by minority communities.

(D) Prevention & Control of Communal Riots

(13) *Prevention of communal incidents*

In the areas, which have been identified as communally sensitive and riot prone districts and police officials of the highest known efficiency, impartiality and secular record must be posted. In such areas and even elsewhere, the prevention of communal tension should be one of the primary duties of the district magistrate and superintendent of police. Their performance in this regard should be an important factor in determining their promotion prospects.

(14) *Prosecution for communal offences*

Severe action should be taken against all those who incite communal tension or take part in violence. Special court or courts specifically earmarked to try communal offences should be set up so that offenders are brought to book speedily.

(15) *Rehabilitation of victims of communal riots.*

Victims of communal riots should be given immediate relief and provided prompt and adequate financial assistance for their rehabilitation.

Chapter 4

Scheme Of Infrastructure Development for Schools or Institutions

Scheme Details

Name of Scheme:	Scheme for Infrastructure Development in Minority Institutes (IDMI)
Name of Supporting Agency:	Department of School Education & Literacy
Address of Supporting Agency:	Ministry of Human Resource Development, Govt. of India New Delhi 110001
Contact Number:	91-11-23383936-744
Email Address:	dsel-mhrd@nic.in
Website:	http://mhrd.gov.in/idmi

Description of Scheme:

IDMI has been operationalised to augment Infrastructure in Private Aided/Unaided Minority Schools/Institutions in order to enhance quality of education to minority children. The salient features of IDMI scheme are:-

- i. The scheme would facilitate education of minorities by augmenting and strengthening school infrastructure in Minority Institutions in order to expand facilities for formal education to children of minority communities.
- ii. The scheme will cover the entire country but, preference will be given to minority institutions (private aided/unaided schools) located in districts, blocks and towns having a minority population above 20%
- iii. The scheme will inter alia encourage educational facilities for girls, children with special needs and those who are most deprived educationally amongst minorities.
- iv. The scheme will fund infrastructure development of private aided/unaided minority institutions to the extent of 75% and subject to a maximum of Rs. 50 lakhs per

Chapter 4

Scheme Of Infrastructure Development for Schools or Institutions

Scheme Details	
Name of Scheme:	Scheme for Infrastructure Development in Minority Institutes (IDMI)
Name of Supporting Agency:	Department of School Education & Literacy
Address of Supporting Agency:	Ministry of Human Resource Development, Govt. of India New Delhi 110001
Contact Number:	91-11-23383936-744
Email Address:	dse1-mhrd@nic.in
Website:	http://mhrd.gov.in/idmi
Description of Scheme:	<p>IDMI has been operationalised to augment Infrastructure in Private Aided/Unaided Minority Schools/Institutions in order to enhance quality of education to minority children. The salient features of IDMI scheme are:-</p> <ol style="list-style-type: none"> i. The scheme would facilitate education of minorities by augmenting and strengthening school infrastructure in Minority Institutions in order to expand facilities for formal education to children of minority communities. ii. The scheme will cover the entire country but, preference will be given to minority institutions (private aided/unaided schools) located in districts, blocks and towns having a minority population above 20% iii. The scheme will inter alia encourage educational facilities for girls, children with special needs and those who are most deprived educationally amongst minorities. iv. The scheme will fund infrastructure development of private aided/unaided minority institutions to the extent of 75% and subject to a maximum of Rs. 50 lakhs per

institution for strengthening of educational infrastructure and physical facilities in the existing school including (i) additional classrooms, (ii) science / computer lab rooms, (iii) library rooms, (iv) toilets, (v) drinking water facilities and (vi) hostel buildings for children especially for girls.

Scholarship/Stipend Offered:

Application Procedure:

Documents Required:

Last Date of Application: --

Eligibility Criteria

Main Criteria:

A Domicile of: Any

Gender: Both

Category: General

Minimum Age:

Maximum Age:

Marital Status:

Minimum Education: Other

Other Qualification: Others

Health

Physical Disability: None

Occupation

Occupation:

Economic Condition: NA

Minimum Family Income:

Maximum Family Income:

Chapter 5

Scheme Of Infrastructure Development Private Aided/Unaided Minority Institutes (IDMI)

(Elementary Secondary / Senior Secondary Schools)

Introduction:

National Policy on Education (NPE) has adopted the concept of a national system of education, implying that all students irrespective of caste, creed, language or sex have access to education of comparable quality. The Policy lays special emphasis on removal of disparities and equalizing educational opportunities by attending to the specific needs of those who have remained educationally backward so far.

1. In pursuance of NPE stipulations, the scheme of Area Intensive Development for ensuring an area intensive approach to education was launched in the IXth Plan. This scheme was merged with Madrasas Modernisation Scheme during the Xth Plan with two components of Modernisation and Infrastructure remaining separate. No financial assistance for infrastructure development was envisaged for Madrasas to whom assistance was restricted to providing honorarium for the teachers teaching modern subjects and assistance under the infrastructure component was provided to Governmental and Non Governmental educational institutions imparting modern education.
2. Two components of infrastructure and modernization are sought to be demerged in the XIth Plan in view of the fact that the target groups for these two components are different. The component of Modernization of Madrasas has been recast and a separate scheme of providing quality education in Madrasas drawn up. The infrastructure component is proposed to be incorporated in this scheme - Infrastructure Development of

private aided/unaided Minority Institutes (IDMI) (elementary secondary/senior secondary schools).

Objective:

4. The scheme would facilitate education of minorities by augmenting and strengthening school infrastructure in Minority Institutions (elementary/ secondary/senior secondary schools) in order to expand facilities for formal education to children of minority communities. The scheme will inter alia encourage educational facilities for girls, children with special needs and those who are most deprived educationally amongst minorities.

Coverage:

5. The scheme will cover the entire country. However, preference will be given to eligible minority institutions (private aided/unaided elementary/ secondary/ senior secondary schools) located in districts, blocks and towns having a minority population above 20%, based on available census data.

Financial Pattern:

6. An amount of Rs.125 crore is proposed for the scheme in the XIth Five Year Plan.
7. The scheme will fund infrastructure development of private aided/unaided minority elementary/secondary/senior secondary schools to the extent of 75% and subject to a maximum of Rs. 50 lakhs per school for:
 - i. Strengthening of educational infrastructure and physical facilities in the existing elementary/secondary/senior secondary school including additional classrooms, science / computer lab rooms, library rooms, toilets, drinking water facilities etc.
 - ii. Hostel buildings for children in such category of schools, especially for girls.
 - iii. Any other educational infrastructure not covered in (i) or (ii) above, but which in view of the State/Central Grant

private aided/unaided Minority Institutes (IDMI) (elementary secondary/senior secondary schools).

Objective:

4. The scheme would facilitate education of minorities by augmenting and strengthening school infrastructure in Minority Institutions (elementary/ secondary/senior secondary schools) in order to expand facilities for formal education to children of minority communities. The scheme will inter alia encourage educational facilities for girls, children with special needs and those who are most deprived educationally amongst minorities.

Coverage:

5. The scheme will cover the entire country. However, preference will be given to eligible minority institutions (private aided/unaided elementary/ secondary/ senior secondary schools) located in districts, blocks and towns having a minority population above 20%, based on available census data.

Financial Pattern:

6. An amount of Rs.125 crore is proposed for the scheme in the XIth Five Year Plan.
7. The scheme will fund infrastructure development of private aided/unaided minority elementary/secondary/senior secondary schools to the extent of 75% and subject to a maximum of Rs. 50 lakhs per school for:
 - i. Strengthening of educational infrastructure and physical facilities in the existing elementary/secondary/senior secondary school including additional classrooms, science / computer lab rooms, library rooms, toilets, drinking water facilities etc.
 - ii. Hostel buildings for children in such category of schools, especially for girls.
 - iii. Any other educational infrastructure not covered in (i) or (ii) above, but which in view of the State/Central Grant

in Aid Committee is justified for educational advancement of the minority institution.

Eligibility Conditions:

8. Voluntary organizations / societies / trusts running institutes/schools that are recognized by Central or State governments shall be eligible to apply for assistance under the scheme.
9. Only those voluntary agencies, which have been in existence for a minimum of three years, would be considered for assistance under this scheme.
10. Voluntary organizations eligible under the scheme should:
 - have a proper constitution or Articles of Association;
 - have a properly constituted managing body with its powers and duties clarified in the constitution
 - be in a position to secure the involvement, on voluntary basis, of knowledgeable persons for furtherance of their programmes; not be run for the profit of any individual or a body of individuals;
 - not discriminate against any person or group of persons on the ground of language or sex etc;
 - not function for the furtherance of the interests of any political party; nor in any manner incite communal disharmony.
11. The institute/school for which assistance is being sought should have been functioning for at least 3 years and have substantial enrolment of children from the minority communities. The institution/school should not be a commercialized school charging high fees.
12. The application of the voluntary organization will be addressed to the concerned Secretary of the State/UT, who will be the Chairperson of Grant-in-Aid committee in the State/UT

Implementation And Monitoring:

13. The scheme will be implemented through the State Government. All requests for financial assistance entertained by the State Government in the prescribed application form appended at Annexure will be considered on merit first by the State level Grant-In-Aid committee. The State Government will draw up and notify criteria for prioritization of applications under this scheme and give it wide publicity. The criterion should consider the specific status of minorities in that State/UT and give priority to (i) direct educational infrastructure requirements by which enrolment and retention of minority children in the school/institution is likely to increase, (ii) encourage education of girls, children with special needs and children from the more educationally backward minorities in the State, (iii) the State level Grant-in-Aid Committee will recommend cases of voluntary organizations and the specific schools/ institutions to be assisted, to the Central Government in order of priority. A lower priority should be accorded to institutions / schools / minority organizations that have already received funds under the erstwhile scheme of AIMMP, during the 10th Plan.
14. On receipt of proposals from the State governments the G1AC of the Central Govt, will consider them on merit and recommend assistance
15. A Grants-in-Aid Committee (GIAC) under the Chairmanship of Union Secretary, School Education & Literacy would be constituted for the purpose, with Joint Secretary concerned as Member-Secretary and FA(HRD) as member. It shall have representatives from Ministry of Minority Affairs and State Governments concerned. The Ministry of HRD will nominate two eminent educationists from amongst Minorities to the GIAC. The GIAC will examine and approve the proposals of the State and UT Governments.
16. The financial assistance will be provided on a one time basis. A voluntary organization or educational institution can receive benefit from the scheme only once in five years. Funds will be released in two installments by GOI through the State Government. The second installment will need to be claimed within one year of the first installment during which period

the 25% share of the minority institution, should have been contributed to the infrastructure up-gradation.

17. Voluntary Agencies receiving the assistance would be required to furnish audited details of expenditure made in the prescribed Performa duly attested by a chartered accountant/the competent authority.
18. The grant will be admissible to only those organizations/institutions which submit the updated statement of accounts for all the grant-in-aid received by them under this scheme in the past, duly certified by a chartered accountant.
19. Monitoring reports regarding the voluntary organizations receiving assistance will indicate, total number of beneficiary students, amount received and utilized by the institutions, shall be furnished to the Ministry of Human Resource Development Government of India on an annual basis by the State Government, after obtaining the same from voluntary organizations receiving assistance under the scheme.
20. The accounts/records of activities of the voluntary organization shall be available on demand for inspection to Central/State Government/CEAG.
21. The Central & State Governments will widely publicize the scheme.
22. The performance of the scheme will be evaluated by the Central & State Governments as appropriate but definitely once after completion of two years of its operation.
23. No claim will be entertained from any organizations/individual for consideration as a permanent beneficiary since the scheme is to be implemented on purely voluntary basis envisaging onetime non-recurring financial assistance.

Chapter 5a.
Application Form Of Development for Infrastructure in
Minority Educational Institutions of Elementary/
Secondary and Higher Secondary Level

PART-1

(To be filled by the applicant)

1	Name of Voluntary Organisation/Society managing the school (With complete address):	
2	Name with address of the school/ institution for which financial assistance is required:	
3	Objects and activities (give brief history of the organisation/society managing the school :)	
4	Specific activities of the school for which financial assistance is sought under the scheme:	
5	Whether registered under the Central/State Board? If yes, Registration No. (A copy of the registration certificate to be enclosed):	
6	Organizational structure, total staff, their roles and responsibilities, staff turnover of educational institute/ school for which assistance is being sought and the voluntary organization / society:	
7	Governing Board/Managing Committee- number of members, their role, meeting held and attendance, their involvement in decision making of educational institution/school and the voluntary organization/society concerned (List of members may be enclosed):	

Benefits of Minority for Education Institutions

8	Name and address of bankers, auditors, legal advisors (including details of accounts) of voluntary organization / society.	
9	<p>Details of infra-structural facilities available with educational institution /school for whom assistance is being sought:</p> <p>a) Whether the building is rented or own?</p> <p>b) No. of rooms available for classes and Administrative purposes:</p> <p>c) Sufficiency of accommodation for teaching modern subjects:</p> <p>d) whether separate rooms for science laboratory, library etc., are available:</p> <p>e) No. of teachers subject-wise already working with their name, qualifications etc. (if needed attach sheets)</p> <p>f) Number of children enrolled in respective classes relevant to the purpose for which assistance is being sought [at least 3 years data be given)</p> <p>g) Number of girl students be given in (f) above</p>	
10	Action Photographs about the school:	
11	Success stories / testimonials / awards / recognitions and how the work of school has made difference to the individual, family and for the community:	
12	Community/client involvement in the academic affairs of school/educational institution:	
13	Future plans and sustainability:	

14	Audited balance sheet, income and expenditure statement for the last three years of voluntary agency and educational institution/school for which assistance is sought:		
15	Annual Report if any of VA/educational institution or school:		
16	Information on existing funding sources with break up of grants, loans, and corpus received by VA and educational institution/school for which assistance is being sought:		
17	Whether the educational institution/school is receiving financial assistance for infrastructure development of any kinds from any other source; if so the details thereof:-		
18	Amount required for additional		
	Item	Number	No. of children to be benefited
	a) Classrooms		
	b) Science rooms		
	c) Computer lab rooms		
	d) Library rooms		
	e) Toilets (Girls)		
	f) Toilets (Boys)		
	g) Drinking water facilities		
	h) Hostels for girls		
	i) Hostels for boys		
	j) Educational facilities like ramps /labs for children with special needs		

k) Any other educational infrastructure requirement			
TOTAL:			
* Amount required for physical infrastructure should not be more than State PWD schedule of rates			
19	Voluntary Organization/Society's share, equal to 25% towards item 18 and commitment of Voluntary Organization/Society to provide the same:		
20	Source of investment of voluntary organizations' / society's share given against item 18		
21	Central Govt share equal to 75% required against item 18.		

It is certified that the information furnished above is true and I am personally liable for any misrepresentation or error.

Date:

Place:

Signature of President/Chairman/Secretary

Benefits of Minority for Education Institutions

k) Any other educational infrastructure requirement			
TOTAL:			
<i>* Amount required for physical infrastructure should not be more than State PWD schedule of rates</i>			
19	Voluntary Organization/Society's share, equal to 25% towards item 18 and commitment of Voluntary Organization/Society to provide the same:		
20	Source of investment of voluntary organizations' / society's share given against item 18		
21	Central Govt share equal to 75% required against item 18.		

It is certified that the information furnished above is true and I am personally liable for any misrepresentation or error.

Date:

Place:

Signature of President/Chairman/Secretary

PART - II**(Recommendation of The State Grant-in-Aid Committee)**

Sr. No.	Name of the Organization whose case is being recommended	Yes / No
1.	Whether State govt has drawn up & disseminated a criteria for prioritization of applications under this scheme	Yes / No
2.	Whether proposal has been received in the specified application form as prescribed?	Yes / No
3.	Whether the proposal being recommended for financial assistance, is in accordance with this criteria?	Yes / No
4.	Whether proposal has been scrutinized and is in accordance with the eligibility and financial parameters of the scheme?	Yes / No
5.	Whether the organization has legal rights to land on which infrastructure is being proposed under this scheme?	Yes / No
6.	Whether estimates for the proposed infrastructure are not more than the State PWD schedule of rates?	Yes / No
7.	Whether it has been ascertained that the organization being recommended for funding is not duplicating funds received from other State/Central Govt schemes/ programmes for the same purpose?	Yes / No
8.	Whether the organization whose case is being recommended, has the furnished the audited accounts, utilization certificates, annual report & any other performance report as specified, which was due till date of forwarding of case?	Yes / No
9.	The Order of Priority in which the case of the organization is being recommended?	[give number in figure & words]

The application has been examined and it is certified that the organization is eligible for assistance and has the capability of taking up a programme applied for.

(Signature of the Member Secretary of State GIAC)

Chapter 6

Schemes Of Research and Studies

1. Introduction

- a) Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) under the Central Sector Scheme 'Scheme of Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes including Publicity' shall provide professional charges to those Research Organizations/ Institutions/ Councils/ Civil Societies/ Universities including Deemed Universities, Reputed Institutions of higher learning, Autonomous Bodies/ Market Research Agencies and Registered Bodies of professionals (henceforth called Research Organizations) which have the expertise and are willing to undertake purposeful Operation Research/ Market Research/ Action Research:
- On the problems and requirement of minorities including baseline surveys/surveys;
 - Carrying out concurrent monitoring on the implementation of various schemes undertaken for minorities; and
 - To provide professional charges to Government agencies and reputed private media agencies and Media Management Agency to carry out Information, Education and Communication (IEC) activities through multi-media campaign including print, electronic and other media.
- b) Reports of such Operation Research/ Market Research/ Action Research including baseline surveys/surveys are expected to provide information and data on development deficits, successful schemes, strategies and approaches worth replicating, suggest specific programme interventions and policy options, etc.
- c) Concurrent monitoring is also essential for enabling mid-course corrections to ensure effective implementation of programmes and schemes.

- d) Financial support will also be extended to organization(s) holding Workshop/Seminar/Conference provided the theme of workshop / seminar / conference has direct relevance to the mandate of the Ministry.
- e) Financial support will not be provided to any organization for holding Workshop/Seminar/Conference for formulation of research proposal. No funding will be given to any organization for holding any group discussion.

2. Objectives

- a) To generate information and database on problems and requirements of Minorities through Operation Research/ Market Research/ Action Research.
- b) To collect information about development deficits through Baseline Surveys.
- c) Concurrent Monitoring of schemes being implemented by the Ministry.
- d) To formulate Annual Media Plan and carry out IEC activities through Multi media campaign involving Print media, electronic media and Outdoor Publicity for dissemination of information to generate awareness relating to schemes/ programmes and initiatives for Minorities.
- e) To give wider publicity to Prime Minister's 15 Point Programme for Welfare of Minorities and Multi-sectoral Development Programme (MsDP), which are flagship programmes of this Ministry.
- f) To support organization for workshops/ seminars/ Conferences on the subjects relevant to minorities.

3. Scope

- A. The scheme covers expenditure for Operation Research/ Market Research/ Action Research including baseline survey/survey, monitoring/ concurrent monitoring and evaluation studies of various schemes and programmes of the Ministry including the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities throughout the

- country with special focus on Minority Concentration Districts/blocks/towns/cluster of villages and holding workshop / seminar/conference on themes of direct relevance to the Ministry which are either proposed by the institutions/organizations themselves or proposed/sponsored by the Ministry itself.
- B. The scheme also covers development of Monitoring formats and performance indicators of the scheme to be developed by respective Divisions implementing the scheme. Empanelled agencies may be used for this purpose also following General Financial Rules (GFRs).
- C. For Information, Education and Communication (IEC) activities, creative multi-media campaign for dissemination of information relating to programmes, schemes and initiatives of the Ministry of specialized nature requiring professionalism, expertise and infrastructure normally not available with Government agencies, would be carried out through reputed private media agencies by following relevant provisions of General Financial Rules (GFRs). Special focus would be given to publicity of the Prime Minister's New 15 Point Programme.
- D. A "Media Management Agency", may be engaged by the Ministry following General Financial Rules. This agency will be responsible for IEC activities through multimedia campaign by print, electronic, cyber media etc. and also for branding of the schemes of the Ministry. It would also advice the Ministry on the time and timelines of the activities to be undertaken and through which media.
- E. Efforts would be made to carry out intensive multi-media campaign with focus on districts, blocks and cities/cluster of villages having a substantial minority population. This does not limit the scope of IEC activities only for minority population, but also includes awareness creation for all sections of society in general to have a multipronged approach to extension activities. For multi media campaign to be carried out by agencies empanelled with DAVP and other government agencies, proposals will be invited and considered

directly by the Ministry by following the provisions of General Financial Rules to ensure cost effectiveness and transparency.

- F. Advertisements for National Commission for Minorities (NCM) may also be considered in the media campaign after due approval of Competent Authority in the Ministry.
- G. For content creation for media campaign, agencies empanelled with DAVP will be engaged at DAVP rates by the Ministry.

4. Eligibility

- A. The following categories of Research Organizations are eligible for professional charges under the scheme for undertaking Operation Research/ Market Research/ Action Research, monitoring/concurrent monitoring, evaluation and baseline survey/survey and holding workshop / seminar /conference:-

- Research Organizations/ Institutions/ Councils.
- Registered Civil Societies under Societies Registration Act.
- Universities including Deemed Universities recognized by University Grant Commission (UGC).
- Reputed Institutions of higher learning.
- Autonomous Bodies.
- Reputed Market Research Agencies and Registered Bodies of professionals.

Reputed Media agencies empanelled with DAVP and National Film Development Corporation (NFDC) would be eligible for making creative multi-media campaign of specialized nature requiring professionalism, expertise and infrastructure normally not available with Government Ministries/ Departments/ PSUs/ Autonomous bodies under the agencies of different Government Departments/ Ministries.

5. Guidelines For Submission Of Proposals

A.1 Proposals for Operation Research/ Market Research/ Action Research

Including baseline survey/survey, monitoring/concurrent monitoring, evaluation may be invited either through advertisement in the newspaper and website of the Ministry or directly from Research Organization of the Government or may be proposed/sponsored directly by the Ministry itself. This can also be done with empanelled agencies with the Ministry following relevant provisions of GFRs. In case of special circumstances, the Ministry may also engage a Research Organization as per procedure laid down in GFR. Assistance given by the Ministry will be institution-based and released to the head of the Research Organization. Staffs appointed for a study are deemed to be employees of the Research Organization.

A Research Organization eligible and desirous of undertaking Operation Research/ Market Research/Action Research including survey and concurrent monitoring under this scheme will apply to the Ministry in the prescribed format (Appendix-I) along with an outline of the proposed project in accordance with the following broad guidelines:-

- i. **Objectives:** The focus and orientation as well as specific objectives spelt out in detail.
- ii. **Justification:** A precise identification of the problem, the hypothesis to be tested and the question to be answered.
- iii. **Relevance to an action programme:** A statement in concrete terms as to how the results of the study will be relevant to improvement in formulation and implementation of the policy, plan or programme for minorities.
- iv. **Approach and methodology:** The extent to which the study is reflective or empirical; whether it is intended to collect primary data and if so, based on a sample survey or a case study; relevant sources or necessary data if the use of available data is envisaged.

- v. **Details of data collection and analysis:** Concepts, definitions, important variables, sampling design if necessary, broad contents of schedules/questionnaires of relevant lines of analysis, tabulation, programme and synopsis of chapter plan of the report, if possible.
- vi. **Project Duration:** Time required for completing the study and submission of the report, period envisaged for preparation, field study/collection of data and drafting of the report. Research study should normally be completed within the duration of six months and in any case not beyond a period of one year. A Memorandum of Understanding (MoU) will be signed with Terms of Reference (ToRs) and Penal Clauses in place to expedite project completion.
- vii. **Staffing pattern:** The number and types of supporting staff, the period for which are required and remuneration to be paid.
- viii. **Budget:** Financial requirements broken down under different items of remuneration of staff, TA, workshops/seminars, stationery/printing of forms, computation and contingencies.
- ix. **Institute's contribution:** The extent of contribution proposed by the institution/organization towards the cost of undertaking the study.
- x. **Bio-data of staff:** Detailed information about the academic qualifications and research experience of the Project Director and the senior staff to be associated with the study. This is not required in the case of institutions/council/organization of the Government.

A.2 Proposals for Workshop/Conference/Seminar

May be invited either through advertisement in the newspaper or website of the Ministry or directly from Research Organizations of the Government or may be proposed/sponsored directly by the Ministry itself. Relevant provisions of GFRs would be followed in all these procedures. Research Organizations whether in Government/ Semi-Government or private sector eligible and desirous of organizing workshops / seminars / conferences will apply to

the Ministry with an outline of the proposed project with following details:

1. The main topic/theme of the workshop/seminar/conference etc.;
2. Significance /purpose indicating clearly the contribution which the proposed workshop/seminar/conference is expected to make;
3. Subjects/contents proposed for discussion;
4. Level of participants and their number;
5. Duration and venue;
6. Programme Schedule;
7. Tentative Resource Persons;
8. Collaborating Agency, if any;
9. Financial Projections and estimates;
10. Experience of the Organization in the field (if any).

B. The Ministry may invite applications for making creative multi-media campaign of specialized nature requiring professionalism, expertise and infrastructure normally not available with Government agencies through advertisement in newspapers and website of the Ministry or from the list of reputed private media agencies empanelled with DAVP. For selection of the private media agencies not empanelled with DAVP, the procedure laid down in GFR and the guidelines issued from Ministry of Finance (Department of Expenditure) from time to time will be followed. The proposals would be examined by a Screening Committee. The Creative agencies will submit proposal(s) with following details:

- a. Name of the agency.
- b. The Medium to be used.
- c. Address of the agency, Permanent Head Quarter, Regional Office (if any), Contact person, e-mail, Telephone number
- d. Whether empanelled with DAVP.
- e. Details of the proposal.

- f. Extent of circulation in case of print media/ Television Rating Points (TRP) in case of electronic media.
- g. Coverage of the campaign.
- h. Target group/s.
- i. Expected contribution of the proposed creative campaign in IEC activities.
- j. Financial implications. It should be with all the detailed break up indicating name of medium, mode of publicity, time duration, rate and total cost (with taxes if any).

6. Screening of Proposals

- A. On receipt of proposals from Research Organizations for Operational Research/ Market Research/ Action Research, baseline survey/survey, monitoring, evaluation/concurrent monitoring, the following Committee shall examine and consider the proposals in the meeting:

1.	Joint Secretary (Respective Joint Secretary in-charge of the concerned Division)	Chairman
2.	Representative of IFD, MoMA	Member
3.	Representative of Planning Commission	Member
4.	Representative of Central Statistical Organization (CSO)	Member
5.	Representative of National Sample Survey Organization (NSSO)	Member
6.	Director / Deputy Secretary dealing with PM's 15 Point Programme and Ms DP / Dir (SS) / Dir. (Wakf) as nominated by the Chairperson	Member
7.	Director/Deputy Secretary (Research and Media)	Convener

* The final approval of the selected agency will be obtained from the Secretary, Minority Affairs.

- B. On receipt of proposals for Workshop / Conference / Seminars, following Committee shall examine and consider the proposals:

1.	Joint Secretary (Respective Joint Secretary in-charge of the concerned Division)	Chairman
2.	Representative of IFD, MoMA	Member
3.	Director / Deputy Secretary dealing with PM's 15 Point Programme and MsDP / all Directors / Deputy Secretaries dealing with different Schemes of the Ministry	Member
4.	Director/Deputy Secretary (Research and Media)	Convener

* The final approval of the selected agency will be obtained from the Secretary, Minority Affairs.

- C. The proposals for Media Plan received from Directorate of Advertisement and Visual Publicity (DAVP), All India Radio (AIR), Doordarshan and National Film Development Corporation (NFDC) will be examined by the Ministry and final Plan will be drawn up by the Media Division, which will be approved by the Minister of Minority Affairs. The Media Division may take inputs from the other Divisions with regard to the content.
- D. The proposals received from private media agencies as per media plan, will be examined by following Screening Committee:

1.	Joint Secretary (in-charge of Research, Media)	Chairman
2.	Representative of IFD (MoMA)	Member
3.	Director, DAVP	Member
4.	Director, Ministry of Information and Broadcasting	Member
5.	All Directors/Deputy Secretaries of different Divisions in the Ministry	Member
6.	Director (Media), Ministry of Minority Affairs	Member Secretary

- B. On receipt of proposals for Workshop / Conference / Seminars, following Committee shall examine and consider the proposals:

1.	Joint Secretary (Respective Joint Secretary in-charge of the concerned Division)	Chairman
2.	Representative of IFD, MoMA	Member
3.	Director / Deputy Secretary dealing with PM's 15 Point Programme and MsDP / all Directors / Deputy Secretaries dealing with different Schemes of the Ministry	Member
4.	Director/Deputy Secretary (Research and Media)	Convener

* The final approval of the selected agency will be obtained from the Secretary, Minority Affairs.

- C. The proposals for Media Plan received from Directorate of Advertisement and Visual Publicity (DAVP), All India Radio (AIR), Doordarshan and National Film Development Corporation (NFDC) will be examined by the Ministry and final Plan will be drawn up by the Media Division, which will be approved by the Minister of Minority Affairs. The Media Division may take inputs from the other Divisions with regard to the content.
- D. The proposals received from private media agencies as per media plan, will be examined by following Screening Committee:

1.	Joint Secretary (in-charge of Research, Media)	Chairman
2.	Representative of IFD (MoMA)	Member
3.	Director, DAVP	Member
4.	Director, Ministry of Information and Broadcasting	Member
5.	All Directors/Deputy Secretaries of different Divisions in the Ministry	Member
6.	Director (Media), Ministry of Minority Affairs	Member Secretary

* The final approval of the selected agency will be obtained from the Secretary, Minority Affairs.

7. Pattern of Assistance

A.1. The Ministry will bear the expenditure on the following approved items of expenditure connected with the Operation Research/ Market Research/ Action Research including baseline survey/survey, evaluation/concurrent monitoring:-

- a. Remuneration for project staff.
- b. Travelling and Daily Allowances for project staff.
- c. Stationery and printing of questionnaires, schedules and forms.
- d. Workshop/seminar.
- e. Contingencies including postage charges, computation and tabulation charges.
- f. Survey, Data Collection, Processing, Presentation. All the above mentioned items will be included in the total project cost.

A.2 The Ministry will bear the expenditure on the following items of expenditure connected with workshop / seminar / conference, whenever necessary.

(i)	Travelling and daily allowance for participants.
(ii)	Honorarium (specifying purpose).
(iii)	Stationery/ Information booklets.
(iv)	Contingencies including postage charges/Fax charges/telephone charges
(v)	Publication of the seminar/workshop papers.
(vi)	Proceedings.
(vii)	Miscellaneous, if any.

All the above mentioned items will be included in the total project cost. In case of Workshop/Seminar / Conference, Rs. 1.25 lakh will be admissible for 50 participants for one day workshop / conference / seminar. A maximum of 200 participants for two days

workshop will be admissible in a given proposal. The cost includes arrangement of place for workshop/seminar, reading material for participants in bags / folders, boarding / lodging expenses of resource persons / outstation participants (if any), honorarium to resource persons, publicity, overheads (limited to 2.5% of the total budget provided for workshop / seminar) and preparation of report on the outcomes of workshop / seminar.

The publications of the Reports of workshops / seminars / conferences by the organization will be done in consultation with the Ministry.

- B. In respect of multi-media campaign/publicity, the pattern of assistance will be based on the approved Media Plan.
- C. Provisions not exceeding 1.5% of the total budget will be made to meet the administrative and allied costs viz. management of the scheme, engagement of personnel/consultant etc.

8. Quantum of Assistance.

- A.1 The professional charges would be released in the case of Operation Research/ Market Research/ Action Research/ Survey in three installments; first installment - 40% on approval, second installment - 40% on submission of draft report and third installment - 20% on acceptance of final report by the Ministry.
- A.2 Professional charges would be released in the case of workshop/seminars/conference in two installments, first installment - 90% and the second installment - 10% after the workshop / seminar / conference is over and on receipt of the report and the audited statement of accounts.
- B. The quantum of professional charges in respect of multi-media campaign/publicity will be based on the Media Plan for the year concerned.
- C. Provisions not exceeding 1.5% of the total budget will be made to meet the administrative and allied costs viz. management of the scheme, engagement of personnel / consultant etc.

9. Funding

The Scheme is a 100% Central Sector Scheme implemented by Ministry of Minority Affairs. Total proposed cost of the Scheme is Rs. 220.00 Crore for the 12th Five Year Plan.

10. Terms & Conditions

The following "General Conditions" will be complied with by the Research Organization receiving assistance under this scheme for Operation Research/ Market Research/ Action Research including baseline survey/survey, concurrent monitoring & evaluation and Workshops/ Seminars/ Conferences:

- i. The Research Organization will maintain the accounts and get the final accounts audited by Government empanelled auditors in case of institutes whose accounts are audited by Government empanelled auditors or by a Chartered Accountant, as the case may be, and submit these to the Ministry, along with the Utilization Certificate on the completion of the assignment.
- ii. The Research Organization will not accept or apply for any professional charges from any other source towards the assignment approved under this scheme.
- iii. Separate account will be kept of the project receipts and expenses even though some of the items of expenditure may be common with that incurred by the institution/organization of other activities.
- iv. The Research Organization will be required to prepare a quarterly progress report (except in case of Workshops/ Seminars/ Conferences) on the study and submit the same to the Ministry along with a statement of expenditure actually incurred during the quarter. It will also be required to record a certificate to the effect that the expenditure has been incurred in accordance with the sanctioned grant.
- v. The accounts/documents etc. relating to the project for which professional charges have been provided will be made available for inspection by an officer authorized by the Ministry. The accounts relating to the project shall be open to

audit also by the Comptroller and Auditor General of India or his nominee(s) at his discretion.

- vi. The Research Organization shall prepare and maintain records of all assets acquired solely or substantially out of the funds received under the scheme. Such assets shall not be disposed, encumbered or utilized for other purpose without prior sanction of the Ministry.
- vii. The Project Director of the Research Organization will be required to give an undertaking with Performance Guarantee in writing duly signed by him/her to undertake the Operation Research/ Market Research/ Action Research /survey/ baseline survey/ concurrent monitoring/evaluation and complete it in time. Memorandum of Understanding (MoU) will be signed with Research Organizations and Research Organizations will be given Terms of Reference (TOR) with reference to work assigned to them.
- viii. Delay in completion of the assignment may cause reduction in the professional charges as per the decision of the Ministry taken by the Secretary (Minority Affairs). This penalty may be to the extent of maximum 10% of the total professional charges as agreed between Ministry of Minority Affairs and Research Organizations.
- ix. The Project Director shall submit the final report (with 10 additional copies) to the Ministry within the stipulated duration of study/survey. Normally, Operation Research/ Market Research/ Action Research etc. under this scheme would be expected to be completed within the duration of six months and in any case not beyond a period of one year. Final report will include the problem studied, the procedure followed - methodology of study/survey/monitoring/evaluation, an account of the population studied/surveyed, description and analysis of data, findings, conclusion and policy recommendations/ intervention (if required).
- x. The final report on the study will be evaluated by an Expert Committee to be set up by the Ministry and such reports as recommended and accepted for publication shall be published by the Ministry. The copyright in respect of all reports shall

vest in the Government of India. In case, the Research Organization desires to publish the report on its own, prior permission of the Ministry shall be taken. Ministry may decide on this issue after taking legal opinion. The Ministry would have the sole rights over the research material and data so collected.

- xi. The Research Organization shall be liable to refund the entire grant amount together with damages and interest at the rate prescribed in General Financial Rules or decided in consultation of Controller of Accounts in the Ministry for any violation of the terms and conditions mentioned in the Scheme/Government sanction, from the date of encashment of the cheque /bank draft/e-transfer for the amount sanctioned for the project, provided that the Government in its discretion may relax the date for the purpose of calculation of interest to provide for such interest to be charged or on a subsequent date. Ministry reserves the right to take legal opinion w.r.t. calculation of interest and effective date for imposition of interest.,
- xii. The decision of the Secretary, Minority Affairs on the question whether there has been breach or violation of any of the terms and conditions mentioned herein as well as in the sanction letter, shall be final and binding on the Research Organization.
- xiii. For all disputes, the Court of Jurisdiction will be Delhi only.

11. Mid Term Appraisal

Mid term appraisal of the scheme will be taken up in 2015-16

Chapter 6a

Form for Submission of Proposals for Operation Research/ Market Research/ Action Research/ Survey

I. Institutional Particulars

- i)
 - (a) Name of the Institution/Organization with Head Quarter and Regional Office address (if any)
 - (b) Mailing Address
 - (c) Telephone No.
 - (d) Name of President/Secretary /Contact Person of the organization
- ii) Title of the Project with scope and coverage of area/field.
- iii) Status of the Institution/Organization
Professional organization/social service research organization /autonomous bodies/registered body of professionals/ University /Deemed University (to be stated specifically)
- iv) Nature and functions of the Institution / Organization. (attach the copy of concerned document)
- v) Manner in which the Institution/Organization was established. (Act of Parliament/Act of State Legislature / Registered under Societies Registration Act, 1860)
- vi)
 - (a) In case established under any Act of Parliament/State Legislature, the name of the Statute, Number of Act and year.
 - (b) In case established under the Societies Registration Act, the place, registration number and date of registration.
- vii) I semi-Government Institution/Organization/PSU, the name of the Government Department to which it is attached.
 - (a) Whether Institution/Organization has regular source of income.
 - (b) Whether it runs on no profit no loss basis.

- ix) Brief history of the Institution/Organization, its objective and activities/academic pursuits in case of individuals.
- x) (a) Whether the Institution/Organization has any previous experience in the field of welfare of Minorities in the country/or undertaken similar activities;
(b) If so, detail thereof.
- xi) Details of infrastructure available with organization.

II. Project Outline

- i. Objective.
- ii. Justification.
- iii. Relevance of the action Programme.
- iv. Approach and Methodology.
- v. Details of Data collection and analysis.
- vi. Project duration.
- vii. Staffing pattern.
- viii. Budget.
- ix. Institutions/organization's own contribution.

III. (1) Staffing Pattern

- i. Name of the Project Director
- ii. Position held by the Project Director in the Institution/Organization mentioned in Item 1(i) and elsewhere, at present.
- iii. Major Positions held by Project Director previously.
- iv. Curriculum vitae of the Project Director (to be attached).
- v. Field of specialization of Project Director.
- vi. Projects completed by Project Director previously and organization for which undertaken.
- vii. List of publications in last 3 years period (to be attached).
- viii. Names of other Projects in hand of the Project Director and names of their commissioning agencies.

- ix) Brief history of the Institution/Organization, its objective and activities/academic pursuits in case of individuals.
- x) (a) Whether the Institution/Organization has any previous experience in the field of welfare of Minorities in the country/or undertaken similar activities;
(b) If so, detail thereof.
- xi) Details of infrastructure available with organization.

II. Project Outline

- i. Objective.
- ii. Justification.
- iii. Relevance of the action Programme.
- iv. Approach and Methodology.
- v. Details of Data collection and analysis.
- vi. Project duration.
- vii. Staffing pattern.
- viii. Budget.
- ix. Institutions/organization's own contribution.

III. (1) Staffing Pattern

- i. Name of the Project Director
- ii. Position held by the Project Director in the Institution/Organization mentioned in Item 1(i) and elsewhere, at present.
- iii. Major Positions held by Project Director previously.
- iv. Curriculum vitae of the Project Director (to be attached).
- v. Field of specialization of Project Director.
- vi. Projects completed by Project Director previously and organization for which undertaken.
- vii. List of publications in last 3 years period (to be attached).
- viii. Names of other Projects in hand of the Project Director and names of their commissioning agencies.

IV. (2) Other Staff

(Number of persons employed, designation, pay, duration of employment to be specified); in case of senior staff, bio-data may be attached.)

S. No.	Name Staff	Designation	Age	Sex	Date of employment	Monthly Pay / Remuneration

V. Budget Estimates**(a) Details of Budget**

S.No.	Items of Expenditure	Units	Rate (in Rs.)	Total Cost (in Rs.)	Remarks
1.	Remunerations				Breakup to be given as per format given below in IV (b)
2.	Travel Cost				
3.	Data Collection / processing / Analysis				
4.	Stationary, printing, postage etc.				
5.	Over Heads/ Contingency Cost				Permissible up to 3% of the total project cost
	Total Cost				

(b) Remuneration of Staff

S.No.	Category of Staff	Number	Job/ Task to be performed	Duration	Monthly remunerations (in Rs.)	Total Cost
1.	Project Director					
2.	Research/ Survey Staff					
3.	Field Staff					
4.	Secretariat Staff					
	Total					

VI. List Of Documents To Be Attached With Each Copy Of Application Form

1. Copy of Registration Certificate of Organization.
2. Memorandum of Association and Rules/Constitution
3. Composition of Board of Governors/Executives or Governing Body
4. Audited Accounts of Last three years with Auditor's report.
5. Latest Annual Report.
6. Copies of the reports published by organization in the period of last three years.

Place:

Date:

(Name and Signature of the
President/Secretary of the Institution
/ Organization) Official Stamp

Chapter 6b

Form for Submission of Proposals for Workshops/ Seminars/ Conferences

I. Institutional Particulars

- i.
 - a) Name of the Institution/Organization with Head Quarter and Regional Office address (if any)
 - b) Mailing Address
 - c) Telephone No.
 - d) Name of President / Secretary / Contact Person of the organization
- ii. Title of the Project with scope and coverage of area/field.
- iii. Status of the Institution/Organization Professional organization /social service research organization / autonomous bodies/ registered body of professionals/University/ Deemed University (to be stated specifically)
- iv. Nature and functions of the Institution/Organization. (attach the copy of concerned document)
- v. Manner in which the Institution/Organization was established. (Act of Parliament/Act of State Legislature/Registered under Societies Registration Act, 1860)
- vi.
 - (a) In case established under any Act of Parliament/State Legislature, the name of the Statute, Number of Act and year
 - (b) In case established under the Societies Registration Act, the place, registration number and date of registration.
- vii. If semi-Government Institution/Organization/PSU, the name of the Government Department to which it is attached.
- viii.
 - (a) Whether Institution/Organization has regular source of income.
 - (b) Whether it Runs on No Profit No Loss Basis.

- ix. Brief history of the Institution/Organization, its objective and activities/academic pursuits in case of individuals.
- x. (a) Whether the Institution/Organization has any previous experience in the field of welfare of Minorities in the country/or undertaken similar activities;
(b) If so, detail thereof.

II. Details of infrastructure available with organization.

III. Details of The Proposal

- a. The main topic / theme of the workshop / seminar / conference etc.;
- b. Significance/purpose indicating clearly the contribution which the proposed workshop / seminar / conference is expected to make;
- c. Subjects/contents proposed for discussion;
- d. Level of participants and their number;
- e. Duration and venue;
- f. Programme Schedule;
- g. List of tentative Resource Persons with their expertise;
- h. Collaborating Agency, if any;
- i. Financial Projections and estimates;

IV. Experience of the Organization in the field (if any).

V. Profile of Project Coordinator.

VI. Budget Estimates - As per para 7 A.2 of the guidelines

VII. List of documents to be attached with each copy of application form

- 1) Copy of Registration Certificate of Organization.
- 2) Memorandum of Association and Rules/Constitution
- 3) Composition of Board of Governors/Executives or Governing Body
- 4) Audited Accounts of Last three years with Auditor's report.
- 5) Latest Annual Report.
- 6) Copies of the reports published by organization in the period of last three years.

Place:

Date:

(Name and Signature of the
President /Secretary of the Institution/
Organization) Official Stamp

Chapter 6c

Application Form of Schemes for Research and Studies

Research/ Market Research/ Action Research/ Survey

I. Institutional Particulars

- i)
 - a) Name of the Institution/Organization with Head Quarter and Regional Office
 - b) Mailing Address address (if any)
 - c) Telephone No.
 - d) Name of President/Secretary /Contact Person of the organization
- ii) Title of the Project with scope and coverage of area/field.
- iii) Status of the Institution/Organization Professional organization / social service research organization / autonomous bodies / registered body of professionals / University / Deemed University (to be stated specifically)
- iv) Nature and functions of the Institution/Organization. (attach the copy of concerned document)
- v) Manner in which the Institution/Organization was established. Act of Parliament / Act of State Legislature / Registered under Societies Registration Act, 1860)
- vi)
 - (a) In case established under any Act of Parliament / State Legislature, the name of the Statute, Number of Act and year
 - b) In case established under the Societies Registration Act, the place, registration number and date of registration.
- vii) If semi-Government Institution / Organization / PSU, the name of the Government Department to which it is attached.
- viii)
 - (a) Whether Institution/Organization has regular source of income.
 - (b) Whether it runs on no profit no loss basis.
- ix) Brief history of the Institution/Organization, its objective and activities/academic pursuits in case of individuals.

- x) (a) Whether the Institution/Organization has any previous experience in the field of welfare of Minorities in the country/or undertaken similar activities;
(b) If so, detail thereof.
- xi) Details of infrastructure available with organization.

II. Project Outline

Objective.

Justification.

Relevance of the action Programme.

Approach and Methodology.

- Details of Data collection and analysis.
- Project duration.
- Staffing pattern.
- Budget.

Institutions/organizations own contribution.

III. (1) Staffing Pattern

- i) Name of the Project Director
- ii) Position held by the Project Director in the Institution /Organization mentioned in Item 1 (i) and elsewhere, at present.
- iii) Major Positions held by Project Director previously.
- iv) Curriculum vitae of the Project Director (to be attached).
- v) Field of specialization of Project Director.
- vi) Projects completed by Project Director previously and organization for which undertaken.
- vii) List of publications in last 3 years period (to be attached).
- viii) Names of other Projects in hand of the Project Director and names of their commissioning agencies.

(2) Other Staff

(Number of persons employed, designation, pay, duration of employment to be specified); in case of senior staff, bio-data may be attached.)

Benefits of Minority for Education Institutions

S. No.	Name Staff	Designation	Age	Sex	Date of employment	Monthly Pay / Remuneration
S. No.	Items of Expenditure	Units	Rate (in Rs.)	Total Cost (in Rs.)	Remarks	
1.	Remunerations				Breakup to be given as per format given below in IV (b)	
2.	Travel Cost					
3.	Data Collection /processing/ Analysis					
4.	Stationary, printing, postage etc.					
5.	Over Heads/ Contingency				Permissible up to 3% of the total project cost	
	Total Cost					
1.	Project Director					
2.	Research/ Survey Staff					
3.	Filed Staff					
4.	Secretariat Staff					
	Total					

1. Copy of Registration Certificate of Organization.
2. Memorandum of Association and Rules/Constitution
3. Composition of Board of Governors/Executives or Governing Body
4. Audited Accounts of Last three years with Auditor's report.
5. Latest Annual Report.
6. Copies of the reports published by organization in the period of last three years.

Place:

Date:

(Name and Signature of the President/Secretary
of the Institution/Organization)
Official Stamp

Chapter 7

Application Form for Minority Status Certificate

1. (a) Name and address of the institution
(b) Name and address of the President/ Secretary of the Trust/ Society
2. Whether the applicant institution's claim is based on religious or linguistic minority?
3. Whether the applicant institution has been established or administered by: -
 - (a) Religious minority or
 - (b) Linguistic minority
4. Whether any competent authority in the State/ UT has been authorized to issue minority status certificate to minority educational institutions. If so, furnish details.
5. Whether an application has been moved with the authority concerned? If yes, attach a copy of your application with the following information:
 - (a) Date of application
 - (b) The application:
 - (i) Is rejected
 - (ii) Is still pending.
 - (c) In case of rejection, the reason therefore.
(Attach a copy of the order or rejection letter)
 - (d) The date on which the order of rejection has been communicated to you.
6. If your application is still pending, what is the current status of your application.
7. Date(s) of reminder(s) sent by you to the competent authority and replies received, if any, in this regard.

Benefits of Minority for Education Institutions

8. Details pertaining to the Society/ Trust
 - (a) Name and Address of the Society/ Trust
 - (b) Whether it is registered (attach a copy of the certificate of registration)
 - (c) Attach a copy of the MOA of Society/ Trust deed
 - (d) Name and addresses of the founding Members/ Mutwallis/ Trustees and their religion.
 - (e) Whether the MoA of the Society/ Trust Deed has been amended at any time and, if yes, attach a copy of the amendments.
9. Details pertaining to the Institution
 - (a) The year in which the institution has been established
 - (b) Who established the institution
 - (c) Percentage of students from the minority community admitted in the institution (show community-wise break-up of student population admitted in the institution in current academic year through an affidavit of the Principal / Headmaster / Headmistress).
 - (d) Names and Addresses of the present Trustees/ Mutwallis/ Members of the Governing Body and their religion.
 - (e) Whether the Trust/ Society of the applicant institution has been recognized by any court or competent authority as Religious/ Linguistic minority institution? If yes, provide details.
 - (f) Whether the minority status of the applicant institution has been withdrawn by the competent authority at any time. If yes, on what grounds.
 - (g) Whether the name of the institution or its ownership has changed since its inception and if so the details thereof.
 - (h) Have you ever approached any judicial forum including Supreme Court or High Court regarding minority status certificate? If so, furnish details and give present status.

- (i) Is the institution affiliated to the State Board or Central Board or University. Furnish details including copy of order/ letter of affiliation.

10. Whether the institution is aided / un-aided

DECLARATION

I, _____ Chairman/Secretary/Correspondent on behalf of the _____ Society, hereby aver that the particulars furnished above are true to the best of my knowledge and that if any detail is found on verification/ inspection to be otherwise, the institution shall forfeit the minority status certificate awarded to it. The decision of the Commission in this regard shall be final.

Chairman / Secretary / Correspondent
(for and on behalf of the Institution)

Place:

Date:

Chapter 8

Application Form To Be Submitted By Coaching Institutes For Receiving Grants-In-Aid

(To be filled in by an authorized representative of the applicant organization) **PART-I**

1	Name, address, telephone No. Fax No. /e-mail ID	
2	Address and telephone no. of the functional Centre for which the application is being submitted.	
3	for profit or Commercial; or Registered society or Trust etc.)	
4	Date of establishment	
5	<p>Whether registered under the Societies Registration Act, 1860 / as a Public Trust / as a Company:</p> <p>Give name of the Act under which registered</p> <p>Registration no. and date of Registration (Please attach an attested photocopy thereof)</p> <p>Period up to which valid</p>	
6	<p>Previous years achievement of coaching/ training institute (if any):</p> <p>(i) For new cases (applying for release of First Installment) :</p>	

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Year	Total number of students coached for (i) competitive examinations for government jobs (ii) entrance examinations for admission in technical and professional courses (iii) employment in private sector	Number of students succeeded in (i) competitive examinations for government jobs (ii) entrance examinations for admission in technical and professional course (iii) getting jobs in the private sector	% of success

(ii)	<p>Year-wise details of students/candidates coached viz- name, father's name, sex, date of birth, educational qualification, permanent address, telephone number, bank account etc.</p> <p>(Please enclose the list of students/candidates coached for</p> <p>(i) competitive examinations for Government jobs</p> <p>(ii) entrance examinations for admission in Technical and Professional courses and</p> <p>(iii) Private jobs, separately and indicate against them the successful candidates.)</p>	
7	<p>(a) Details of the coaching Institution/Center:</p> <p>Constitution of Board of Management/Governing Body etc. and the particulars of the Member:</p>	

Benefits of Minority for Education Institutions

Sr.No.	Name	Address	Occupation

Details of Faculty Members:

Sr.No.	Name	Qualification	Experience	Subject taught

<p>Constitution/Memorandum of Association and Bye-Laws of the Organisation / Institution (copy may be enclosed)</p> <p>copy of Annual Report may be enclosed (if available) -----</p> <p>Income & expenditure Statement and Balance sheet for previous years (if applicable) as certified by the Chartered Accountant or Government Auditor may be enclosed</p> <p>Indemnity bond in prescribed format on Rs.20 stamp paper:</p> <p>Authorization letter in prescribed format for sending grant-in-aid/funds directly into the bank accounts of the Organization:</p> <p>Certified that the institution has not received any other grant for the same purpose from any other Ministry/Department of the Government of India, State/UT Government and any other Government/Non-Government Organization.</p>	
--	--

PART-II

Infrastructure Details Centre-Wise

1	Space available with the institution for coaching Total area covered Number of class rooms own building or in a rented accommodation Details of library facility available with the coaching institution (if applicable)	
2	Infrastructure available for coaching Audio-visual aids Photocopiers Computers Others (as applicable)	
3	Coaching/Training course for which the grant is applied for:	
4	Duration of the programme (Indicate the Probable date of commencement and completion)	
5	Total number of candidates belonging to five notified minority communities proposed to be coached/trained Outstation: Local: Total:	
6	Consolidated amount of fee per candidate for each examination / course	

Benefits of Minority for Education Institutions

Examination	Duration of coaching	No .of candidates belonging to minorities proposed to be coached		Total maintenance allowance (@Rs. 3,000 p.m. for outstation and Rs.1,500 p.m.)	Coaching fee	Total amount (Coaching Fee and maintenance allowance)
				For local candidates)		
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
		Outsta tion	Local		Rate per candidate	Total amount

It is certified and agreed that the terms and conditions of the scheme have been read, understood and are acceptable to the Organization.

Place:

Date:

Signature

(a) Full Name of Secretary/President

(b) Name of the Institution/Organization

(Office Stamp, Tel.No.)

Details of documents attached

Chapter 9

FAQs in General for Educational Institutes

Q.1 What is the definition of the term 'Minority'?

Ans: The word 'Minority' is derived from the Latin word 'minor' and the suffix 'ity' which means small in number. According to Encyclopedia Britannica, 'Minorities' means 'groups held together by ties of common descent, language or religious faith and feeling different in these respects from the majority of the inhabitants of a given political entity'.

Q.2 What are the basic principles for claiming minority status?

Ans: The benefits of Article 30(1) can be claimed by the community only on proving that it is a religious or a linguistic minority and the institution was established by them.

Q.3 What is a 'Minority Trust' ?

Ans: A Registered Trust which is run by Minority Community is a 'Minority Trust.' A Jain Trust is eligible for Minority Recognition if, 0% or more of the Founder Trustees are Jains by religion.

Q.4 Is it mandatory for all the board members / Trustees to belong to the Jain Community, for the recognition?

Ans: No. If 50% of the total founders of the trust are Jains, the Trust can be recognized as a Minority Trust.

Q.5 What procedure must be adopted to acquire the 'Minority Recognition'?

Ans: The first attempt must be made to make the formal application using the attached Application Form along with all the required documents to the concerned Divisional Education Officer. After receiving the recommendation from the Divisional Education Officer, the same must be forwarded to the respective Board of Education (Higher / Secondary etc). After receiving the recommendation, the same must be forwarded to the State Government (Ministry of Education), who will give the final decision. Help from the respective State Minority Commission can also be

acquired. A copy of the same must also be sent to FJEI and the respective State Minority Commission. The list of all State Minority Commissions & their addresses is available with FJEI.

If, after a period of 3 months from the date of submission, there is no reply from the authority, the same may be followed up by written letters & finally, a legal case may be put up in the respective High Courts.

Q.6 What is the final indication that the Institute is recognized as a 'Minority Institute'?

Ans: Once the institute has applied the relevant authority, after verifying the claim the State Government gives certificate of Status and registers its name in the minority institution register.

Q.7 Are the benefits in terms of Administration for private - aided & private - non-aided, institutes different? What is the difference?

Ans: Yes, the Private institutes are grouped into - Aided & Unaided, especially for considering the benefits of the Minority Status. The Private Unaided institutes can decide their own procedures & systems as regard to the administration of the institute, whereas the Private Aided institutes, have dependency on the State with regard to some of the administrative rights. (Details in 'Benefits' section of this document)

Q.8 Where in the Constitution is the matter related to 'Minorities' mentioned?

Ans: Only twice, in the Constitution, does the word 'Minority' appears. In article 29 & Article 30. (Statements mentioned above).

Q.9 Which type of education can be incorporated in the Article 30?

Ans: Primary, Secondary, Higher & Professional Education comes under the purview of the definition under Article 30 of the constitution.

Q.10 Can the admission of students to Minority Educational Institutes be regulated by the State Government or by the University to which the institution is affiliated?

Ans: Admission to students to Unaided Minority Educational Institutions, viz. schools where scope of merit based selection is practically nil, cannot be regulated by the State or the University (except for providing the qualifications and minimum conditions of eligibility in the interest of academic standards).

However, the right to administration, not being an absolute one, there could be regulatory measures for ensuring educational standards and maintaining excellence thereof.

In the matter of admissions to undergraduate colleges, and the professional institutions, it would be governed by Article 29(2) and would not then be able to refuse admission on grounds of religion, race, caste, language or any of them.

In the case of Aided Professional Institutions, it can also be stipulated that passing of CET held by the State agency is necessary to seek admission.

Q.11 Which States in the country have declared the 'Jain Community' as a 'Minority Community' (Religious) in their states through GRS?

Ans: The following states have declared the Jain Community' as a 'Minority Community' (Religious) in their states through GRs.

1. Maharashtra-GR Available
2. Madhya Pradesh-GR Available
3. Chattisgarh-GR Available
4. Uttar Pradesh-GR Available
5. Uttaranchal-GR Available
6. Jharkhand
7. Karnataka

However, educational institutions in the remaining states can also claim recognition of 'Minority Status' by using the relevant procedure mentioned in this document.

Q.12 Is it compulsory to grant admissions to Minority Students only or can it also impart education to other children?

Ans: The Minority Educational Institute, can impart education to all the children, of any community, and still acquire the 'Minority Status'.

Q.13 In case of admissions to Jain Students, is it mandatory to fill in the prescribed percent of seats (50%)? In case, so many students cannot be selected, what are the repercussions?

Ans: It is not mandatory to fill in the prescribed percent of seats from the students of the Minority Community. However, if the seats are vacant, they have to be surrendered to the open / reserved category as per the guidelines of the State Government.

Q.14 What are the programs for minority's education?

Ans: The National Policy on Education 1986, incorporates the following programmes for the welfare of Minorities:

15-Point Programme

1. Encourage starting of coaching classes in minority educational institutions to train persons to compete successfully in these examinations.
2. Set up ITI s and Polytechnics by Private Agencies in minority areas to encourage admission of minorities.
3. Training programmes for principals / managers / teachers in Minority School.
4. Guidelines for recognition of Minority Managed Institution & its implementation.
5. Review of Text Books from the stand point of National Integration.
6. Programmes identified for State Governments.
7. Various programmes for Primary, Middle & Higher Secondary & Higher Education.
8. Various programmes for Vocational, Technical, Women's Education.

9. Voluntary effort in Adult Education & Early Childhood Education.
10. Libraries, Reading Rooms & Extension Work
11. Scheme for Scholarships.
12. Bench Mark Survey & Research Studies
13. Association with Boards of Education & other Advisory Bodies.
14. Monitoring, Review & Evaluation Arrangements

Q.15 What are the rights of minorities to administer Educational institutions?

Ans: The Administrative rights incorporate:

1. Choosing the managing or governing body
2. Choosing the Teachers & Non teaching staff
3. Selection & Admission of students
4. Use the properties and assets for the benefit of its own institution
5. Prescribing fee
6. Take disciplinary action against its staff
7. To use its properties and assets for the benefits of the Institution

Q.16 What are the statutory measures regulating standards?

Ans: An institution seeking Minority Recognition must fulfill the statutory requirements concerning the academic standards, the qualification of teachers and of the students seeking admission. It must have the financial resources and the capability to run on sustainable basis & maintaining the prescribed standard of education.

Q.17 Is there any restriction on the medium of instruction in minority educational institutions?

Ans : The State Government or the University is not empowered to prescribe the medium of instruction to be followed by the

minority educational institute. However, in case of institutes receiving aid, there are certain standards to be observed.

Q.18 Whether the institution can grant any consideration to the students of minority class in matters of admission?

Ans : The Aided Minority Institute has the freedom to give special consideration to students of their own community in matters of admission. The Government cannot enforce the rules of reservation in favor of SC/ST & OBC Classes for admission of students in these institutes.

However, the maximum limit for admission, qualification & procedure (minimum percentage for admission) for Aided Institutes is prescribed by the respective State Government and must be adhered to.

Q.19 Are there any rules related to the appointments of teachers in minority Educational institutes?

Ans: The Government cannot enforce the rules of reservation in favor of SC/ST & OBC Classes for the posts of teachers and other staff in minority educational institutes.

Q.20 What are the benefits to educational institutes after acquiring the minority status?

Ans: The various Administrative Benefits are:

The State or the concerned Government will have a greater say in giving admissions to students of the Minority Community (Jain). The prescription of percentage has to be done by the Govt. according to the local needs and different percentages can be fixed for Minority Unaided Institutes & Professional Colleges.

The private unaided educational institutes have the right to choose and select the students who can be admitted to their course of studies. However, it must follow some identifiable or reasonable method of admitting the students.

The Maharashtra Government Guidelines on Admission of Students of Minority Community to Minority Recognized institutes states that 50% seats of the admission capacity from amongst eligible students will be allowed to be filled for the Minority Students. These seats shall be filled either by

conduction of test or on the basis of merit of qualifying examination.

These institutes can admit any Jain student within and outside the country.

The Minority Managed & Recognized Educational Institution shall have the freedom to appoint any qualified candidate (Teacher) / non-teaching staff / Principal / Head Master / Director also by following its own procedure & methods of selection.

Teachers in such institutions must possess requisite qualifications.

The Jain Minority Institutes can prescribe its own statutes for service conditions of teaching & non teaching staff, provided the statutes are not inconsistent with the existing laws and their principle of natural justice.

The Minority Educational institutions must be free to induct competent and reputed individuals from other communities in the Managing Committees / Governing Bodies.

It is open to the State to provide conditions for granting recognition or disbursing aid to minority institution. These may include, follow prescribed syllabus for examination, courses or study. The State has the right to provide regulatory provisions for ensuring educational excellence, conditions of employment of teachers, ensuring health, hygiene and discipline and allied matters.

The Government cannot enforce the rules of reservation in favor of Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Communities for admission of students in these Institutions. The Government cannot enforce the rules of reservation in favor of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes for the posts of teaching and other staff in Minority Recognized Educational Institutes.

The State shall not, in granting aid to Educational Institutions, discriminate against any Educational Institution on the ground that is under the management of a minority, whether religious or linguistic.

conduction of test or on the basis of merit of qualifying examination.

These institutes can admit any Jain student within and outside the country.

The Minority Managed & Recognized Educational Institution shall have the freedom to appoint any qualified candidate (Teacher) / non-teaching staff / Principal / Head Master / Director also by following its own procedure & methods of selection.

Teachers in such institutions must possess requisite qualifications.

The Jain Minority Institutes can prescribe its own statutes for service conditions of teaching & non teaching staff, provided the statutes are not inconsistent with the existing laws and their principle of natural justice.

The Minority Educational institutions must be free to induct competent and reputed individuals from other communities in the Managing Committees / Governing Bodies.

It is open to the State to provide conditions for granting recognition or disbursing aid to minority institution. These may include, follow prescribed syllabus for examination, courses or study. The State has the right to provide regulatory provisions for ensuring educational excellence, conditions of employment of teachers, ensuring health, hygiene and discipline and allied matters.

The Government cannot enforce the rules of reservation in favor of Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Communities for admission of students in these Institutions. The Government cannot enforce the rules of reservation in favor of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes for the posts of teaching and other staff in Minority Recognized Educational Institutes.

The State shall not, in granting aid to Educational Institutions, discriminate against any Educational Institution on the ground that is under the management of a minority, whether religious or linguistic.

Q.21 What benefits do Students get, if they are under minority recognized institute?

Ans: The Jain Minority Student is eligible for admission to any Jain Minority Recognized Institute. The advantage is that the Minority institute has 50% seats reserved for Jain Students. On following the prescribed procedure for admission viz. entrance test, group discussion, interview, etc. (as applicable) he/she has a higher priority of getting admission. Also the Minority institute can admit Jain Students from all across the country from any state.

Q.22 If the recognized institute wants to get collaboration with foreign institute are there any provisions for such institutes?

Ans: UGC is framing guidelines in this matter, which will be binding.

Q.23 Whether the members of minority of one state can establish the institute in another state and claim for minority status?

Ans: Yes. The Minority community in one state can establish an institute in another state. However, the community must be a Minority community in the state where he/she establishes the institute. In case of Jains, as the Jain Community is a minority community (0.4% of the total population), it is also a minority community in each of the states. Hence the Minority Recognition can also be sought for such an institute.

Q.24 Are there any leading cases supporting the same issue?

Ans: The list of cases & brief summaries are a part of this document ().

Q.25 Please give the names of books on minority act and grants for Govt. unaided institutes/aided institutes. 2) Give the names and places of publishers Addresses.

Ans: The following Reference books can be used :

Supreme Court on Educational Institutions - 2003

Pub : Hind Law House

Price : Rs. 250/-

Constitutional Law of India - Mr. Sharma

Pub : Rights of Employees in the Schools & Other Educational Institutions managed by Minorities - Mr. M.P. Vashi (Advocate)

Pub : Smt Sudha N. Patkar

Price : Rs. 20/-

(The list of relevant Acts under the Supreme Court & High Courts have been enclosed as a part of this document)

Q.26 In case of a clear vacancy, can the Govt. officials pressurize to take a candidate from their surplus quota, in minority institutes?

Ans : No. The Government cannot enforce its will for recruiting candidates for the teaching & non-teaching staff in the Minority Recognized Institute.

Q.27 In case of Aided institutions who have got the Minority Recognition, is there any right to fill up positions?

Ans : The Minority institute has the right to recruit teaching & non-teaching staff of their choice, provided the same does not contradict with the minimum qualification criterion prescribed by the concerned Board / University.

Q.28 Does the institute, which is certified by State is automatically become minority in Central or separate Permission has to be taken?

Ans: As the Minority Recognition is entirely a State Issue, a separate recognition is necessary in each state.

Q.29 Whether imparting primary education is compulsory for minority status & for minority benefits? Is it necessary to make registration to get minority benefits for primary education.

Ans: No. Minority Status can be received for any type of institute, irrespective of the grade of education, it imparts. However in order to avail the benefits, it is necessary to get the Recognition.

Q.30 Does the Indian Constitution permit 'Jain Religion' as a minority?

Ans: The Constitution is silent about the definition of Jains as Minority. The Constitution does not declare any religion as minority because it is a State affair.

Q.31 If we are an education Trust running three educational institutes, do we require to take minority status only for our Trust or for all the three institutions?

Ans: No. The Minority Recognition, if sought for the Trust / Society which runs institutes, is applicable to all its institutes, however, in some states separate application for each school / college has to be processed. Also, recognition for a school & a degree college / professional college has to be addressed to different authorities.

Q.32 Regarding the appointment of teacher and other staff in a minority institution, is the University approval for selection necessary?

Ans : Yes. For Minority Recognized Educational institute, approval for selection of teachers & other staff is necessary from the education officer / University.

Q.33 What must the institute expect if the minority recognition is refused / answer not received, even after consistent follow up?

Ans: The authority applied to shall communicate in writing the reasons for rejection to the institute. However, if no such written communication is sought, the same must be followed up from the institute, or a writ petition be filed in the respective High Court after consultation with FJEI.

Q.34 What are the types of Limitations that a Minority Recognized institute will face, inspite of being recognized ?

Ans : Limitations do exist even for recognized minority institutes, especially with Aided Educational Institutes, where the State Government directives & Regulations take a priority over the benefits. The limitations concerned with each benefit is mentioned in the document, against individual points.

Chapter 10

FAQs for Linguistics Minorities

Q1. What is meant by minor languages?

Ans: The minority languages are those which are other than the Principal Language in a State. But these may be the major languages which are spoken in other states where they are the Principal Language. Or they may be languages confined to a small region or spoken by a small number of people. We have called these languages "the minor languages". But we have taken the liberty of including other languages which are spoken by a large number of people and in different states over a fairly large area but have not been accepted, due to historical reasons, in either the educational stream or the administration. These languages are still to achieve their rightful potential. We have also included them in the definition of minor languages so as to focus attention on them also. Examples are Santhali, Bhili, Dogri.

Q2. Is not the Commissioner Linguistic Minorities a mere paper tiger?

Ans: A. He is not a paper tiger. In fact he is not a tiger even. Is he a watchdog? No, he is not even that. He is not expected to growl when he detects something amiss. He is actually the conscience keeper of the nation. The safeguarding of the interests of the linguistic minorities is the concern of every authority and the CLM merely points out the deficiencies which the Central and the State authorities should take care of.

Q3. Should the advance registers be maintained in all the schools?

Ans: There are two types of orders in different states. Some states have ordered that all the schools should maintain these registers. Obviously in the areas where the linguistic minorities are not present or are present in very small number, it is not practical to open schools meant for the linguistic minorities. In case the registers are kept there, it is only a formality and there is no point in doing that. In some

states the registers are kept only in the linguistic minorities schools. These schools are in any case teaching the minority languages or through the minority languages and as such there is no point in their maintaining a register exclusively. The correct thing is that such registers should be maintained in all the schools in the areas where the members of the linguistic minorities stay in sufficiently large number. This will help in the readjustment between the schools including the linguistic minorities schools.

Q4. How does advance registration help?

Ans: The number of students in the linguistic minorities schools keep on changing. If advance registers are kept, it will help the education authorities to assess the likely number of students taking up a particular medium/ language and the teachers and the books can be arranged accordingly. It will also help the students and their guardians if they know in advance which school they can go to. Advance registration also involves re adjustment of the students by sending them to a nearby school where the students may be sufficient to warrant teaching through the minority language. The third aspect is that there are some complaints that the students are dissuaded from taking up a particular language by the teacher on the plea that no one else is doing it. If the advance registers are there, such a mischief can be avoided as the information will be readily available and the person concerned need not decide on the spot.

Q5. Does opening schools for linguistic minorities not mean extra burden on the State Governments?

Ans: Yes, there will be some extra expenditure but this will not be so high as to disturb the financial position of the State. Generally the linguistic minorities live in compact areas and opening of minority language school merely means the substitution of one teacher for another. This does not entail extra expenditure. The extra expenditure is involved in some mixed localities where the schools for the linguistic minorities have less students than the other schools. But it is not excessive. Some extra expenditure is also involved in printing of books in the minority languages as the off take is smaller compared to the regional language but cross subsidization can

cover this expenditure without casting any burden on the State.

Q6. Will not the encouragement of minority languages lead to difficulties at higher educational levels?

Ans: No, for we do not exclude the learning of the regional language, the link language or English. In fact the teaching through minority language at the elementary school level will lead to better communication skill (letter writing, essay writing, precise writing) which will spill over to other languages. To facilitate the change over to other languages, suitable bridge courses can be developed.

Q7. Will the encouragement of Minority Languages not lead to factious society?

Ans: No, for we do not exclude the learning of the regional language, the link language or English. In fact the teaching through minority language at the elementary school level will lead to better communication skill (letter writing, essay writing, precise writing) which will spill over to other languages. To facilitate the changeover to other languages, suitable bridge courses can be developed.

Q8. Is there not a minimum requirement for a language to be recognized as a minority language?

Ans: First of all there is no provision for recognition as a minority language. It is automatically defined when it is not the mother tongue of the majority of the people in the state. What is expected is that the areas where there is substantial number of such minority language speakers should be declared. This is based upon the premises that the practical steps which can be taken up for protection of the linguistic minorities will depend upon their proportion in the population. But it does not take away the right of the people whose areas are not so declared. It is to be noted that the number of those who speak the minority language is not material; Nor whether they speak a language included in the eighth schedule or not; Nor whether the language is termed tribal or non tribal

Q9. Is it necessary that a language must have a script before it can be recognized as a minority language?

Ans: Script is not an essential part of the language. A language can exist without a script. In fact a large number of languages have been passed on from one generation to the next orally. Many of the languages have been written in scripts which are not indigenous but either the scripts for other languages have been adopted as such or with some modifications. Many of the languages in the North East are written in Roman script. In Santhali, an altogether new script has been created. Some languages have adopted Devnagari and some others the script of the local majority language. Such adoption does not harm the concerned language and sometimes makes it easier to learn the principal language. It is, however, true that for the educational purposes and for other written communications, script is essential. It will also facilitate the preservation and propagation of the language. It is recommended that the script of the local Principal language should be preferably adopted. Devnagari will also be a good choice. Some modification thereof may be required.

Q10. What happens if the majority of the residents of a state do not have a language which is spoken by a majority of residents?

Ans: Since there is no majority language, all the languages which are mother tongues are minority languages. All the residents belong to linguistic minorities. Examples are Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands.

Q11. Who are the linguistic minorities?

Ans: In each state, there is a language which is the mother tongue of the majority of the residents of that state. All others who do not have that language as their mother tongue belongs to the linguistic minorities.

Q12. What happens if the majority of the residents of a state do not have a language which is spoken by a majority of residents?

Ans: Since there is no majority language, all the languages which are mother tongues are minority languages. all the residents belong to linguistic minorities. Examples are Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands.

Q13. Who are the linguistic minorities?

Ans: In each state, there is a language which is the mother tongue of the majority of the residents of that state. All others who do not speak that language belong to the linguistic minorities. Excluded are the persons whose language is the official language of the state. for example, in Jammu and Kashmir, Urdu speaking persons though numerically in minority are not part of linguistic minorities because Urdu is the official; language of the state.



Chapter 11

Addresses

Following are the addresses of National Commission for Minorities, States Minorities Commission and Names & Addresses of the State Channelising Agencies Of NMDFC for your ready reference.

Chapter 11a

Address Of National Commission For Minorities

Office Address:

National Commission for Minorities,
5th Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi 110 003
Tel. 24615583 Fax 24693302, 24642645, 24698410
Toll Free Number: 1800110088 E-mail: ro-ncm@nic.in

Chapter 11b

Addresses Of States Minorities Commission

No	Name	Address	Telephone/Fax No./Email
1.	Andhra Pradesh	No Commission	Fax-23452114
2.	Assam State Minorities Commission 1. Sh. Abdul Muhib Mazumdar, Chairman 2. Sh. Allen Brooks, Member 3. Dr MuktiDeb Choudhury, Member 4. Sh. Parvez Shah, ACS, Secy. cum AO	Assam State Minorities Commission RGB Road, New Ganeshgudi, Dispur, Guwahati - 781 006.	Ph. 0361-2383000 Mobile -9435345015
3.	Bihar State Minorities Commission 1. Sh. Naushad Ahmed, Chairman 2. Sh. Prahlad Kumar Sarkar, Member 3. Sh. Zaheer Malmali, Member 4. Sh. Razia Kamil Ansari, Member 5. Sh. Liyaqat Ali Mansoori, Member 6. Dr. Islam Rahi, Member 7. Sh. Shamshad Alam, Member	Bihar State Minorities Commission Barrack No. 7, Old Secretariat, Patna - 300 015	Mobile-9431476236 Ph-2213595 Fax-2215051

	<p>8. Mohd. Abdullah, Member</p> <p>9. Sh. T.B.S. Jain, Member</p> <p>10. Mohd. Farooquzzamam, Section Officer</p>		
4.	<p>Chhattisgarh Minorities Commission Sardar Dalip Singh Hora, Chairman Sh. Murtja Vanak, Member Sh. M. R. Khan, Secy</p>	<p>Chhattisgarh Minorities Commission C-186, Shailendra Nagar, Raipur (C.G.) - 492 001</p>	<p>Ph-2434809 Fax-2445073</p>
5.	<p>Delhi State Minorities Commission, Pushpinder Singh, Member A.C. Michael, Member</p>	<p>Delhi State Minorities Commission, 1st Floor, C- Block, Vikas Bhawan, New Delhi- 110002</p>	<p>Tele/Fax- 23370823-25 Email: dmc_nct@rediffmai l.com</p>
6.	<p>Jharkhand Minorities Commission Dr. Shahid Akhtar, Chairman Bhushan Tiarky, VC Yaqoob Ansari, VC Shri Shailendra Singh, Member Md. Eqrarul Hasan, Member Sh. Rafique Anwar, Member Sh. Kari Barkat Ali, Memer Sh. Asgar Misbahi,</p>	<p>Jharkhand Minorities Commission Building No. 3, Artisen Hostel, Sector-3, Dhurwa Ranchi-834004</p>	<p>Ph-0651-2400946 Mobile- 09534212588 Fax-06512400946 Email- chairman@jsmc.in</p>

	Member Shi Samuel Guria, Member Sri Kalyan Bhattacharya, Member		
7.	Karnataka State Minorities Commission 1. Sh. Anwar Manippady, Chairman, 2. Sh. Ateeque Ahmed, Secretary,	Karnataka State Minorities Commission 5th Floor, Vesveshwariah Tower (M) Dr. B.R. Ambedkar Veedhi, Bangalore - 560 001.	Phone- 080 - 2286 4204 / 3400 Fax- 080-2286 3282 Email: secretary@karmin.i n
8.	M.P. State Minorities Commission Sh. Trilochan Singh , Member Sh. Surjit singh Gill, PS to Member	M.P. State Minorities Commission, E-Block, Old Secretariat, Bhopal - 462 011	Ph-0755-2730873 Fax-0755- 2733065
9.	Maharashtra State Minorities Commission 1. Sh. Munaf	Maharashtra State Minorities Commission Behind J.J. School of Arts, Mumbai	22650085 / 22610156

Chapter 11c Names & Addresses of the State Channelling Agencies Of NMDFC	
Andhra Pradesh	Assam
Andhra Pradesh State Minorities Financial Corporation 5th Floor, Haj House, Nampally, HYDERABAD-500 001 (A.P.) Ph. 040-23244500, 23244501 23244368 (Fax)	Assam Minorities Development & Finance Corporation R.G.B. Road, Dispur, GUWAHATI - 6 Ph. 036 1-2595480, 2207373
Bihar	Chandigarh
Bihar State Minorities Financial Corporation Ltd. Haj Bhawan, 1st Floor, 34 Harding Road, Ali Imam Path, PATNA - 800 001 Ph. 0612-224975, 2224975, 2215994 (Fax) www.bsmfcl.org	Chandigarh Scheduled Caste, Backward Classes & Minorities Financial & Development Corporation Ltd. Additional Town Hall Building, 3rd Floor, Sector 17-C, CHANDIGARH. Ph. 0172-2701449, 2707527, 2712797, 2708690 (Fax)
Chhattisgarh	Delhi
Chhattisgarh State Antyavasayee Coop. Finance and Dev. Corpn. Ltd. B-9, Sector-5, Devender Nagar, Raipur, CHHATISGARH Ph. 0771- 4248601-15, 4248617 (Fax)	Delhi SC/ST/OBC Minorities & Handicapped Financial & Dev. Corporation Ltd. Ambedkar Bhawan, Sector - 16, Rohini, DELHI - 110 054 Ph. 011-27570627, 27570502, 27572706, 27572630 (Fax)
Gujarat	Haryana
Gujarat Minorities Finance and Development Corporation 2nd Floor Block No.11, Dr. Jivraj Mehta Bhawan, GANDHINAGAR - 382 010	Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam, SCO 813-14, Sector 22-A, CHANDIGARH - 160 022.

Ph. 079-23253757, 23254581, 23254583, 23254584, 23254152 (Fax)	Ph. 0172-2701722, 2701074, 2707539, 2726826 (Fax) Mewat Development Agency Housing Board Colony, Nuh, (Distt. Mewat) - 122 107. Ph. 01267-271179, 274603, 271461(Telefax)
Himachal Pradesh	Jharkhand
H.P. Minorities Finance and Development Corporation SDA Complex, Block No.3 8, First Floor, Kasumpti, SHIMLA - 171 009. Ph. 0177-2621669, 2621271, 2622164 (Telefax)	Jharkhand State Scheduled Tribes Cooperative Development Corporation Ltd. Balihar Road, Morabadi, RANCHI - 834 008 ,JHARKHAND Ph. 0651-2552398 (Off), 2551686 (Fax)
Jammu & Kashmir	
1st May to 30th October J&K Women's Development Corporation Old Secretariat, Block-A, 1st Floor, SRINAGAR Ph. 0194- 2450432	1st November to 30th April J&K Women's Development Corporation, Hall No.6-B, 2nd Floor, Aquaf Complex, Gandhi Nagar, JAMMU (J&K) Ph.0191-2430321,2439370
J&K Entrepreneurship Development Institute (JKEDI) Sempora, Pampore, Pantha Chowk, SRINAGAR- 191101. Ph. 01933-224362/65/67, 224402 (Fax)	J&K Entrepreneurship Development Institute (JKEDI) Ground Floor, Jawaharlal Nehru Udhyog Bhawan, Railhead Complex, JAMMU - 180 012 Ph. 0191-24745 12, 2477327, 2477329 (Fax)
J&K Entrepreneurship Development Institute (JKEDI) Government Industrial Estate LEH	J&K SCs/STs & BCs Development Corporation Romesh Market, Shastri Nagar, JAMMU - 180 004 0191-2433229, 2451762, 2452009

Kerala	
<p>Kerala State Backward Classes Development Corporation "SENTINEL" 2nd Floor, TC No.27/588 (7) & (8) Pattoor, THIRUVANTHAPURAM - 695 035. Ph. 0471-2577550, 2577539(Fax) www.ksbcd.com</p>	<p>Kerala State Women's Development Corpn. T.C.20/2170, Opp. Manmohan Bungalow, Kowdiar P.O., THIRUVANTHAPURAM - 695 003. Ph. 0471-2727668, 2316006 (Fax), www.kswdc.org</p>
<p>Kerala State Cooperative Federation for Fisheries Development Ltd. Kamaleswaran, Manacaud P.O., THIRUVANTHAPURAM - 695 009. Ph. 0471- 2457172, 2457756, 2458606, 2457752 (Fax) www.matsyafed.org</p>	
Karnataka	Maharashtra
<p>Minorities Development Corporation Ltd. 12th Floor, Main Tower, Dr. B.R. Ambedkar Veedi, BANGALORE - 560 001 Ph. 080- 22861226, 22864720, 22860999, 22864782 (Fax) www.kmdc.in</p>	<p>Maulana Azad Alpsankhyak Aarthik Vikas Nigam DDA Building, 2nd Floor, Old Custom House, Shahid Bhagat Singh Marg, MUMBAI - 400 023 Ph. 022-22633351, 22653080, 22672293, 22672294 (Fax)</p>
Mizoram	
<p>Mizoram Cooperative Apex Bank Ltd. Bazar Bungkawn, PB-138, AIZWAL - 796 001 MIZORAM Ph. 0389- 2312307, 2322744, 2317190, 2327765, 2327764 (Fax)</p>	<p>Zoram Industrial Development Corporation New Secretariat Complex, Khatla, Aizawl, P. Box - 125, AIZWAL - 796 001. MIZORAM Ph. 0389-2310190, 2326271(Fax)</p>

Madhya Pradesh	
<p>M.P. Backward Classes & Minorities Finance and Development Corporation Rajiv Gandhi Bhawan, Parisar-2, 1st Floor, 35, Shyamala Hills, BHOPAL - 462 002, Madhya Pradesh. Ph. 0755-2660209, 2660207-08, 2660390, 2660175 (Fax)</p>	<p>Madhya Pradesh Hastshilp Avam Hathkargha Vikas Nigam Ltd. Hastshilp Bhawan, 03 Hamidia Road, BHOPAL - 462 001. Ph. 0755-2676920, 2676927, 2676928, 2676926 (Fax)</p>
Manipur	Nagaland
<p>Manipur Minorities & Other Backward Classes Economic Development Society Babupara, IMPHAL - 795 001, Manipur. Ph. 0385-2442539, 2451902</p>	<p>Nagaland Industrial Development Corpn. Ltd. IDC House, P.B. No.5, DIMAPUR - 797 112, NAGALAND. Ph. 03862-230571-74, 226473 (Fax)</p> <p>Nagaland Handloom & Handicrafts Development Corporation Ltd., P.B.No.81, Half Nagarajan, DIMAPUR - 797 112, NAGALAND Ph. 03862-224591, 230130, 230046</p> <p>Nagaland State Social Welfare Board New Secretariat Complex, KOHIMA - 797 001, NAGALAND. Ph. 0370-22703 10, 2270307 (Fax)</p>
Orissa	Punjab
<p>Orissa Backward Classes Finance Development Cooperative Corporation Ltd. Q.No. A/6, Unit - 5, Near Rajiv Bhawan, BHUBANESWAR - 751 001. Ph. 0674- 2391061</p>	<p>Punjab State Backward Classes Land Development & Finance Corporation SCO No.60-61, Sector 17-A, CHANDIGARH 160 017. Ph. 0172-2709261, 2705982, 2705995</p>

Puducherry	Rajasthan
<p>Puducherry Backward Classes & Minorities Development Corn. Ltd. No.5, Zamindar Gardens, PUDDUCHERRY - 605 001. Ph. 0413- 2332076, 2225859 (Telefax)</p>	<p>Rajasthan Minorities Finance and Development Corporation Ltd. Ambedkar Bhawan, Plot No.G-3/1, Room No.403/412, 3rd Floor, Near Civil Line Railway Crossing, JAIPUR(Rajasthan) Ph. 0141-2220258, 2220721 (Telefax)</p>
Tamilnadu	Tripura
<p>Tamil Nadu Minorities Economic Development Corporation 807, Anna Salai, Vth Floor, CHENNAI - 600 002. Ph. 044-285 14846, 28515450 (Fax)</p>	<p>Tripura Minorities Cooperative Development Corporation Ltd. Lake Chowmuhani, Agartala, WEST TRIPURA - 799 005. Ph.0381-2326512, 2300083, 2328232 (Fax)</p>
Uttar Pradesh	Uttranchal
<p>U.P. Minorities Financial Development Corpn. Ltd. 746, 7th Floor, Jawahar Bhawan, Ashok Marg, LUCKNOW - 226 001. Ph. 0522-2236976, 2286401, 2286854, 2286053(Fax)</p>	<p>Uttranchal Alpsankhyak Kalyan Tatha Wakf Vikas Nigam 161, Old Nehru Colony, DEHRADUN (UTTRANCHAL). Ph. 0135- 2657747, 2652458, 2652458, 2665228 (Fax) www.alpsankhyak.org.in</p>
West Bengal	
<p>West Bengal Minorities Development and Finance Corporation "AMBER", DD-27/E, Sector-1, Salt Lake City, KOLKATA - 700 064. Ph. 033-23219619, 23212998 www.wbmdfc.org</p>	

Chapter 12

The Gazette of India For Jain Minority

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935

No. 217]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

का.आ. 267(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 खड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 816(अ), दिनांक 23-10-1993 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों के अलावा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 1-1/2009-एनसीएम]

ललित के. पंवार, सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the Jain community as a minority community in addition to the five communities already notified as minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) vide Ministry of Welfare Notification No. S.O. 816(E), dated 23.10.1993 for the purposes of the said Act.

[F No. 1-1/2009-NCM]

LALIT K. PANWAR, Secy.

Chapter 12

The Gazette of India For Jain Minority

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935

No. 217]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

का.अ. 267(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 2 खड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.अ. 816(अ), दिनांक 23-10-1993 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात् मुस्लिम, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों के अलावा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 1-1/2009-एनसीएम]

ललित के. पंवार, सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby notifies the Jain community as a minority community in addition to the five communities already notified as minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) vide Ministry of Welfare Notification No. S.O. 816(E), dated 23.10.1993 for the purposes of the said Act.

[F No. 1-1/2009-NCM]

LALIT K. PANWAR, Secy.

Chapter 13

भारतीय जैन संघठन (BJS) - एक परीचय

भारतीय जैन संघठन (BJS) यह समस्त जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सामाजिक संस्था है। जिसकी स्थापना इसके संस्थापक पूना निवासी श्री. शांतिलालजी मुथ्या ने १९८५ में की। यह संस्था सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक विकास तथा आपदा प्रबंधन क्षेत्र में कार्य कर रही है।

BJS मुख्य रूप से राष्ट्रीय समस्याओं पर अपना लक्ष्य केन्द्रित कर उनके निवारण हेतु गहराईसे अध्ययन कर समाधान प्रस्तुत करने का कार्य तीन दशक से कर रहा है।

BJS में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लगाकर शहर/गांव कार्यकारिणी की शृंखला स्थापित है। संस्था में पदाधिकारियों का चयन चुनाव पद्धति से ना होकर मनोनयन पद्धति से होता है। पदाधिकारियों को मनोनित करने का सम्पूर्ण अधिकार संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। यह कार्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की सलाह से किया जाता है।

वर्तमान में BJS का कार्यक्षेत्र देश के लगभग २० राज्यों में है। संस्था में हजारों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता समर्पण भाव से समाज उत्थान के कार्य में लगे हुये हैं। पूना मुख्य कार्यालय में लगभग ५०० प्रोफेशनल लोग रिसर्च के माध्यम से समाज उपयोगी समाधान के मॉडल्स एवं कार्यक्रम तैयार करने का कार्य बड़ी कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक विकास व आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पिछले तीन दशक में किये गये विशेष कार्य की जानकारी निम्नलिखित है। आपसे विनम्र निवेदन है कि, BJS के कार्यों से जुड़कर देश निर्माण में अपना योगदान दें।

सामाजिक उत्थान

समय काफी तेजीसे बदल रहा है। २५-३० वर्षों में बदलाव की जो रफ्तार रही है, वह पिछले १००-२०० वर्षों में भी अनुभव करने को नहीं मिली। तेजीसे बदलते हुए इस युग में 'परिवार' यह अवधारणा बिखर रही है, तथा इसे बांधे रखने का कार्य अत्याधिक कठिन होता जा रहा है। परिवार ही नहीं बचेंगे, तो समाज का अस्तित्व कैसे रहेगा? इस गंभीर समस्यापर BJS ने, परिवार में रहनेवाले प्रत्येक सदस्य की जरूरतों को समझकर, गहराईसे अध्ययन कर निम्नलिखित समाधान प्रस्तुत किये हैं।

छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम' कक्षा ४थी एवं ८वी के विद्यार्थियों के लिए (Student Assessment Program - SAP 4th & 8th)

तीन घंटे की इस जांच परिक्षा के लिए किसी भी प्रकार की पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी बड़े मजे से, खेल खेल में इस जांच परिक्षा में सहभाग लेते हैं, तथा बड़ी सहजता से पालकों को अपने बच्चों की भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक योग्यता व सामान्यज्ञान, स्वास्थ्य, संबंधित विषयों पर जानकारी प्राप्त होती है। बीजेएस द्वारा, इस कार्यक्रम के माध्यम से, विद्यार्थियों की क्षमता एवं योग्यता का आकलन कर, उन्हें अपनी रुचि अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में, प्राविण्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से, पालकों का विशेष मार्गदर्शन किया जाता है। SAP 4 अब Online www.bjssap.org पर भी उपलब्ध है।

कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम (Carrier Guidance Program)

स्पर्धा के इस युग में, दसवी तथा बारहवी के पश्चात विद्यार्थियों ने कौन से शैक्षणिक क्षेत्र का चयन करना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र भविष्य की शिक्षा के लिए उपलब्ध है, कौन से कॉलेजों का चयन करना चाहिए, उनमें प्रवेश प्राप्त करने की क्या प्रणाली है, पिछले वर्ष का कट ऑफ प्रतिशत क्या था, इत्यादि अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। इस विषय में, जानकारी के अभाव की वजह से, ना ही माता-पिता मदद कर पाते हैं और ना ही स्कूल मदद कर पाता है। आज के दौर में विद्यार्थियों को योग्य कैरियर मार्गदर्शन की अत्याधिक आवश्यकता है। BJS अपने एक्सपर्ट कैरियर मार्गदर्शकों के माध्यम से परिवार की इस जरूरत की पूर्ती हेतु विद्यार्थी एवं पालकों के लिए कैरियर मार्गदर्शन के वर्कशॉप आयोजित करता है।

युवतियों का सक्षमीकरण' - २१ वी सदी की सामाजिक चुनौतियों का सामना करने हेतु Empowerment of Girls to face the social challenges of 21st century (EoG)

आज के इस दौर में, स्कूली शिक्षा पूर्ण कर, उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज में प्रवेश करनेवाली, सोलह से पच्चीस वर्ष की युवतियों के समक्ष अनेक कठिनाईयाँ, आग के समान विक्राल रूप धारण किये खड़ी हैं। जैसे की

अपनेही परिवार में कैसे जीना, माता-पिता से संवाद कैसे करना, नए एवं अच्छे मित्रों का चयन कैसे करना, अपने आत्मविश्वास को टिकाये कैसे रखना, मिडीया-मोबाईल-इंटरनेट के दुष्परिणाम से कैसे बचना, व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान कैसे रखना, पारंपरिक विवाह व प्रेम विवाह के गुण एवं दोष का पूर्व आकलन कैसे करना, इत्यादि अनेक प्रकार की आग आज जमाने में लगी है। इस आग को हम बुझा सकते नहीं। लेकिन इसका सामना करने के लिए युवतियों को प्रशिक्षण के माध्यम से फायर फायटर जरूर बना सकते हैं। यह अत्याधिक महत्वपूर्ण कार्य है। BJS ने अपने तीन दशक के सामाजिक अनुभव के आधार पर, युवतियों को सक्षम करने हेतु, एक्सपर्ट के माध्यम से तीन दिवसीय कार्यशाला तैयार की है। यह कार्यशाला युवतियों को सुरक्षा कवच प्रदान कर, इस सदी की सामाजिक चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनाती है। इस कार्यक्रम के द्वारा ११ राज्यों में १०,००० से अधिक युवतियों का सक्षमीकरण किया गया है। EoG अब Online (www.eogonline.org) पर भी उपलब्ध है।

युवक-युवती परिचय संमेलन (Matrimonial Meet)

योग्य जीवन साथी की तलाश सभी परिवारों की है। परिवार कितनाही समृद्ध क्यों न हो, शिक्षित क्यों न हो, नामी क्यों न हो, योग्य रिश्तों की कमी सभी की है। ढूँढने पर भी योग्य रिश्ते मिल नहीं पाते। नजदीक के रिश्तेदार भी, ना ही रिश्तों की जानकारी देते हैं और ना ही रिश्तों के बीच में पड़ते हैं। रिश्ते ठीक से मिलेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे? रिश्ते ठीक से जुड़ेंगे नहीं तो टिकेंगे कैसे? रिश्ते ठीक से टिकेंगे नहीं तो परिवार आगे बढ़ेंगे कैसे? BJS ने सन १९८५ में इस समस्या को समझा, गहराईसे अध्ययन किया तथा 'परिचय संमेलन' विकल्प के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। एक ही दिन में, एक ही स्थान पर, अपने बेटे या बेटी के लिए, पचास-सौ रिश्ते उपलब्ध करवाने का मंच है, 'परिचय संमेलन'। समाज की जरूरतों को समझते हुए विभिन्न प्रकार के परिचय संमेलन आयोजित किये जाते हैं। जैसे की, प्रोफेशनल परिचय संमेलन, उच्च शिक्षित परिचय संमेलन, सामान्य शिक्षित परिचय संमेलन, शहरी परिचय संमेलन, ग्रामीण परिचय संमेलन, पुनर्विवाह हेतु परिचय संमेलन। पिछले तीन दशक में इन परिचय संमेलनों को अत्याधिक प्रतिसाद मिला है। तथा रिश्ते तय करने में परिचय संमेलन वरदान साबित हुए हैं।

आगामी परिचय संमेलन किन्न शहरों में आयोजित किये जा रहे हैं, इसकी जानकारी www.bjsindia.org वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है।

नव विवाहितों का सक्षमीकरण - सुखी घर परिवार के लिए Empowerment of Couples for Happy Family & Happy Home (EoC)

आज के जमाने में रिश्ते तय होने जितने कठिन हैं, उससे ज्यादा कठिन हैं, रिश्ते निभाना। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी खटपट होने लगी है। खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल, पहनावा आदि में अत्याधिक बदलाव आये हैं। जीने के तौर तरिके बदल गए हैं। पति - पत्नी दोनों ही शिक्षित, उच्चशिक्षित हैं। करियर ने घरेलू कामकाज के ऊपर प्राथमिकता ले ली है। धैर्य, समर्पण, विश्वास, सामंजस्य, सुसंवाद आदि में काफी कमी आयी है, वहीं अहंकार अत्याधिक बढ़ गया है। यही सब वजह है, रिश्तों में दरार की व परिवारों में बिखराव की। भारतीय जैन संघठन के संस्थापक, दूरदृष्टा श्री. शांतीलालजी मुथ्था ने सन २०१० में जैन समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में घोषणा की, कि आनेवाले दस-पंद्रह वर्षों में हर दो विवाह में से एक विवाह टुटेंगा। अगर सही में ऐसा होता है, तो यह समाज के अस्तित्व के लिए अत्याधिक हानिकारक होगा। इस बात को ध्यान में रखकर BJS ने नवविवाहिताओं (विवाह के दस वर्ष तक) में आपसी सौहार्द एवं सामंजस्य स्थापित रहने के दृष्टिकोण से दो दिवसीय कार्यशाला तैयार की है। इस दो दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से नव विवाहित जोड़ो तथा उनके पालकों के आपसी सम्बन्धों में सामंजस्य, बेहतर संवाद, संगठित एवं संयुक्त रहने की भावना, एक दूसरे का विशेष ध्यान, देखभाल, त्याग एवं समर्पण भाव के साथ वैवाहिक और परिवारिक दायित्व एवं सम्बन्धों को विकसित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

व्यवसाय वृद्धि कार्यक्रम (Business Development Program)

परिवर्तन के इस युग में पारंपारिक व्यवसायों में नई पिढी की घटती रूची, पुराने व्यवसायों के अस्तित्व का प्रश्न, मॉल संस्कृति का प्रभाव, व्यवसाय की नई संभावना के प्रति दुर्लक्ष, नई पिढी के कार्यक्षमता का पूरा उपयोग ना होना आदि बातों की वजह से व्यवसाय में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। BJS अपने एक्सपर्ट प्रोफेशनल मार्गदर्शकों के माध्यम से नये एवं पुराने व्यवसायियों के लिए Business & Entrepreneurship Development Program द्वारा मार्गदर्शन करता है।

आगामी परिचय संमेलन किन्न शहरों में आयोजित किये जा रहे हैं, इसकी जानकारी www.bjsindia.org वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है।

नव विवाहितों का सक्षमीकरण - सुखी घर परिवार के लिए Empowerment of Couples for Happy Family & Happy Home (EoC)

आज के जमाने में रिश्ते तय होने जितने कठिन हैं, उससे ज्यादा कठिन हैं, रिश्ते निभाना। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी खटपट होने लगी है। खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल, पहनावा आदि में अत्याधिक बदलाव आये हैं। जीने के तौर तरिके बदल गए हैं। पति - पत्नी दोनों ही शिक्षित, उच्चशिक्षित हैं। करियर ने घरेलू कामकाज के ऊपर प्राथमिकता ले ली है। धैर्य, समर्पण, विश्वास, सामंजस्य, सुसंवाद आदि में काफी कमी आयी है, वहीं अहंकार अत्याधिक बढ़ गया है। यही सब वजह है, रिश्तों में दरार की व परिवारों में बिखराव की। भारतीय जैन संघठन के संस्थापक, दूरदृष्टा श्री. शांतीलालजी मुथ्था ने सन २०१० में जैन समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में घोषणा की, कि आनेवाले दस-पंद्रह वर्षों में हर दो विवाह में से एक विवाह टूटेगा। अगर सही में ऐसा होता है, तो यह समाज के अस्तित्व के लिए अत्याधिक हानिकारक होगा। इस बात को ध्यान में रखकर BJS ने नवविवाहीतों (विवाह के दस वर्ष तक) में आपसी सौहार्द एवं सामंजस्य स्थापित रहने के दृष्टिकोण से दो दिवसीय कार्यशाला तैयार की है। इस दो दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से नव विवाहित जोड़ो तथा उनके पालकों के आपसी सम्बन्धों में सामंजस्य, बेहतर संवाद, संगठित एवं संयुक्त रहने की भावना, एक दूसरे का विशेष ध्यान, देखभाल, त्याग एवं समर्पण भाव के साथ वैवाहिक और परिवारिक दायित्व एवं सम्बन्धों को विकसित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

व्यवसाय वृद्धि कार्यक्रम (Business Development Program)

परिवर्तन के इस युग में पारंपारिक व्यवसायों में नई पिढी की घटती रूची, पुराने व्यवसायों के अस्तित्व का प्रश्न, मॉल संस्कृति का प्रभाव, व्यवसाय की नई संभावना के प्रति दुर्लक्ष, नई पिढी के कार्यक्षमता का पूरा उपयोग ना होना आदि बातों की वजह से व्यवसाय में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। BJS अपने एक्सपर्ट प्रोफेशनल मार्गदर्शकों के माध्यम से नये एवं पुराने व्यवसायियों के लिए Business & Entrepreneurship Development Program द्वारा मार्गदर्शन करता है।

प्लॉस्टिक सर्जरी (Plastic Surgery)

BJS सन १९९० से लगातार, छोटे बच्चों के कटे फटे ओंठ, (Cleft leaf) पलक एवं नाक और कान की बाह्य विकृती, चेहरे के दाग आदि का उपचार निशुल्क प्लॉस्टिक सर्जरी के द्वारा, अमेरिका के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम के माध्यम से कर रहा है। अब तक दो लाख पचास हजार से ज्यादा निशुल्क प्लॉस्टिक सर्जरी BJS द्वारा की गई है।

अल्पसंख्यक सम्बंधित जानकारी (Minority Cell)

२७ जनवरी २०१४ को भारत सरकार ने जैन समाज को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया। अब तक मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, सिख एवं पारसी धर्मों को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था। भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के उत्थान की अनेक योजनाओं के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रूपये का प्रावधान बजट में किया जाता है। जैन समाज के विद्यार्थियों की शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की विविध योजनाएँ, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन की विविध योजनाएँ, युवतियाँ एवं महिलाओं के सक्षमीकरण की योजनाएँ, व्यवसाय के विकास की विभिन्न योजनाएँ, धर्मस्थान की सुरक्षा की विभिन्न योजनाएँ एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से समाज उत्थान की विविध योजनाएँ उपलब्ध है।

BJS द्वारा संकलनीत, निम्नलिखित पुस्तकों के माध्यम से अल्पसंख्यक योजनाओं व लाभ की जानकारी जैन समाज के सभी वर्गों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

- १) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन विद्यार्थियों को लाभ
- २) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन समाज की शिक्षण संस्थाओं को लाभ
- ३) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन समाज की धार्मिक संस्थाओं को लाभ
- ४) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन महिलाओं को लाभ
- ५) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन व्यवसायीयों को लाभ
- ६) अल्पसंख्यक योजनाओं का जैन सामाजिक संस्थाओं को लाभ

यह पुस्तके भारतीय जैन संघठन के मुख्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा www.bjsindia.org वेबसाइट से डाऊनलोड भी कर सकते हैं।

शैक्षणिक विकास

सामाजिक उत्थान के कार्य के साथ साथ, देश निर्माण का कार्य भी भारतीय जैन संघठन की प्राथमिकता रही है। देश निर्माण के कार्य में शैक्षणिक विकास की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः भारतीय जैन संघठन ने इस विषय पर भी अपना लक्ष केंद्रित किया है।

देश में जैन समाज के विभिन्न संस्थाओं द्वारा २५०० शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण १००-१५० वर्ष पूर्व किया गया। इन शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, सभी जाती धर्म के जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा, सेवा के रूप में प्रदान की जाती है। भारतीय जैन संघठन द्वारा सन २००२ में फेडरेशन ऑफ जैन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट (FJEI) की स्थापना की। जैन समाज की १७०० शैक्षणिक संस्थाएँ इस फेडरेशन का हिस्सा हैं। सभी संस्थाओं का अपना अस्तित्व कायम रखते हुए, इन संस्थाओं द्वारा मूल्यआधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विद्यार्थियों तक पहुँचाना ही भारतीय जैन संघठन की प्राथमिकता है। साथ ही साथ, यह मूल्यआधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, देश की १३,००,००० सरकारी एवं प्रायव्हेट स्कूलों में भी लागू करने का ध्येय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए BJS ने निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार कर देश के लिए उपलब्ध किये हैं।

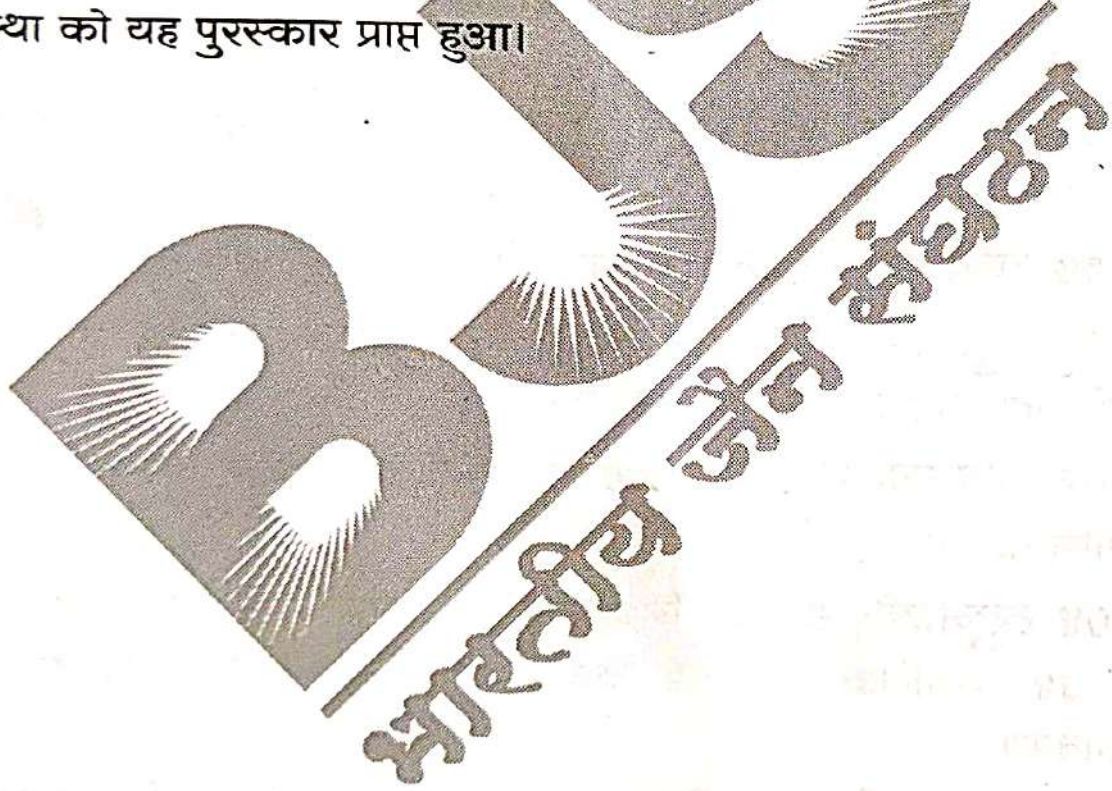
स्कूल अॅसेसमेंट अॅन्ड अॅक्रेडिटेशन (School Assessment & Accreditation)

देश में कॉलेजों की गुणवत्ता का विकास करने की दृष्टिकोण से सरकार ने १९९४ में National Assessment & Accreditation Council (NAAC) का गठन किया। लेकिन ऐसी कोई योजना स्कूलों के लिए उपलब्ध नहीं है। इण्ड ने सन २००४ में स्कूलों के अॅसेसमेंट और अॅक्रेडिटेशन का कार्यक्रम तैयार कर देश की चार हजार से अधिक सरकारी एवं प्रायव्हेट स्कूलों में क्रियान्वित किया। यह कार्यक्रम उपचारात्मक पद्धति का कार्यक्रम है। निर्धारित संकेतको व मानको के आधार पर स्कूल की प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। सुधार के आवश्यक क्षेत्रों का पता लगाता है। स्कूल के मुख्याध्यापक एवं प्रबंध समिति को विशेष सुधार की क्रियाओं से अवगत कराता है। जिससे स्कूल की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है।

भारतीय जैन संघठन ने यह स्कूल अॅसेसमेंट अॅन्ड अॅक्रेडिटेशन कार्यक्रम विभिन्न राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध किये हैं। जिसके माध्यम से उन राज्यों की सरकारी एवं प्रायव्हेट स्कूलों में गुणवत्ता विकास होने में सुविधा

- २०१३ महाराष्ट्र अकाल: महाराष्ट्र के बीड जिले में ११५ सुखा प्रभावित तालाबों का सफाई कार्य (Desilting) मात्र १ माह में किया, २० लाख लिटर पानी की क्षमता इन तालाबों में बढ़ गई। तथा Silt के माध्यम से पांच हजार एकड़ बंजर भूमी को उपजाऊ बनाने का कार्य किया।
- ७ सुखा प्रभावित जिलों में १०,००० पशुओं के लिए २८ पशू शिविरों की स्थापना कर प्रबंधन का कार्य किया।

सन १९९३ से अबतक BJS ने आपदा प्रबंधन के कार्यों की सराहना महाराष्ट्र विधान सभा से लेकर भारत की लोकसभा में की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) व आयआयएम रायपुर ने ३ दिसंबर २०१३ को आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उच्चतम काम करनेवाले ९ संस्थाओं को गौरवान्वित किया उसमें ८ सरकारी संस्थाएँ थी व BJS ही एकमात्र स्वयंसेवी संस्था को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।



BJS Happenings



Leaders of Jain community meeting Law Minister Shri. Kapil Sibal for Jain Minority issue.

Girls giving introduction at a Matrimonial meet



Girls participating in Empowerment of Girls (EOG) programme



Dr. Parag Sancheti, Chairman of Sancheti Hospital, Pune addressing at inaugural programme of "Free Plastic Surgery Camp"



Dr. Raghunath Mashelkar, eminent scientist felicitating a member of recently formed BJS Ex-Student Alumni



Members participating in BJS National Executive Council meeting at Aamby Valley, Lonavla

BJS programmes and activities

Social Development

- ▶ Empowerment of Girls (EOG)
- ▶ Empowerment of Boys (EOB)
- ▶ Empowerment of Couples (EOC)
- ▶ Matrimonial Meet
- ▶ Plastic Surgery Camps
- ▶ Minority Cell
- ▶ Student Assessment Programme (SAP) Std. IV, VIII
- ▶ Career Guidance
- ▶ Mass Marriages
- ▶ Basic Family & Marriage Counseling Course (BFMC)
- ▶ And many more....

Educational Initiatives

School Assessment and Accreditation

- ▶ Process Assessment
 - Critical expert evaluation of school processes for internal improvement plans
 - Based on comprehensive key areas of school operations
- ▶ Profile Classification
 - Placement of School with respect to availability of infrastructure, facilities and human resources
 - Useful for fund-based development planning
- ▶ Grading of school
 - Third party validated report for school's outreach
 - Based on extensive feature list of school
- ▶ Member of CBSE Empanelment for School Quality Assessment and Accreditation

Mulyavardhan- a value education programme

Imbibe universal values and morals and build the character of a child from the formative years.

- ▶ Thorough Design
 - Extensive research on global trends in decline in values & its root causes
- ▶ Innovative Teaching-Learning Methods
 - Emphasis on self evaluation rather than examination for stress free learning
- ▶ Universal applicability
 - Universal context maintained along with the regional flavour
- ▶ Sustainable implementation
 - Covering total 38,000 students of 500 Primary schools of Patoda, Ashti tehsil of Beed & Municipal Corporation school of Jalgaon, Maharashtra

Disaster Response

- ▶ **1993: Latur Earthquake, Maharashtra**
Educational Rehabilitation of 1200 boys (Std V to graduation)
- ▶ **1997: Melghat Malnutrition Project**
Educational Rehabilitation of 350 boys from tribal community for 10 years.
- ▶ **2001: Gujarat Earthquake**
Re-constructed 368 schools in 90 days and handed over to the government.
- ▶ **2002: Akola floods**
Temporary shelters provided to 15,000 victims.
- ▶ **2004: Tsunami**
 - Rescue and relief operations through 6 camps in Tamil Nadu.
 - Constructed 11 schools and 34 primary health centres in 1 year at Andaman & Nicobar islands.
- ▶ **2005: Jammu & Kashmir Earthquake**
870 pre-fabricated shelters despatched for giving refuge to 15,000 affected people.
- ▶ **2008: Bihar floods**
Medical aid to 1,50,000 victims in 181 days.
- ▶ **2013: Maharashtra Drought**
 - Desilting of 115 water bodies in drought-prone district of Beed within a period of one month as a long-term mitigation measure.
 - Establishment and management of 28 cattle camps in 7 drought ridden districts for 10,000 animals.

BJS
भारतीय जैन संघठन

Bharatiya Jain Sanghathan

Muttha Towers, Don Bosco Road, Near Golf Course, Yerawada, Pune - 411 006
Telefax: +91-20- 4120 0600



Email: info@bjsindia.org



Website: www.bjsindia.org



Facebook: www.facebook.com/BJSI